04 - पूंजीवाद चांद सितारों तक

05 - निजी संपत्ति को लेकर यह फैसला मील का पत्थर

A Daily News Magazine

इंदौर

सोमवार, 11 नवंबर, 2024

06 - नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार निर्धारित नहीं, नियमों की अनदेखी भी...

07- 21 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहीं नर्सिंग ऑफिसर

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 45, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्याः MP/IDC/1529/2016-2018)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

डसने लगे हैं ख़्वाब मगर किस से बोलिए
मैं जानती थी पाल रही हूँ संपोलिए
बस ये हुआ कि उस ने तकल्लुफ़ से बात की
और हम ने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए
पलकों पे कच्ची नींदों का रस फैलता हो जब
ऐसे में आँख धूप के रुख़ कैसे खोलिए
तेरी बरहना-पाई के दुख बाँटते हुए
हम ने ख़ुद अपने पाँव में काँटे चुभो लिए
मैं तेरा नाम ले के तज़ब्ज़ुब में पड़ गई
सब लोग अपने अपने अज़ीज़ों को रो लिए
ख़ुश-बू कहीं न जाए प इसरार है बहुत
और ये भी आरज़ू कि ज़रा ज़ुल्फ़ खोलिए
तस्वीर जब नई है नया कैनवस भी है
फिर तश्तरी में रंग पुराने न घोलिए

- परवीन शाकिर

पहली बात

'आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस' और अपराधिक 'जघन्यता' के पैमाने

उमेश त्रिवेदी
संपादक

9893032101

सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार के उदघाटन समारोह में भारत के चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ के सामने एक 'आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस वकील' की मौजूदगी भारतीय विधिक एवं न्याय व्यवस्था के इतिहास में नए अध्याय की शुरूआत है। संग्रहालय का शुभारंभ गुरूवार, 7 नवम्बर 2024 को हुआ था। आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस (एआई) वकील के साथ चीफ जस्टिस के सवाल-जबाब से ज्यादा उसकी तहजीब, तैयारी और तत्परता सुर्खियों में है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस वकील से भारतीय विधिक व्यवस्था में वर्षों से तर्काधीन अनुत्तरित सवाल पूछा था कि 'क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है'? एआई वकील ने सधे सुरों में जवाब देते हुए कहा था कि- 'हां,भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है। यह सर्वोच्च न्यायालय व्दारा निर्धारित दुर्लभतम मामलों के लिए आरक्षित है, जहां अपराध असाधारण रूप से जघन्य किस्म का हो, वहां ऐसी सजा दी जा सकती है।'

एआई वकील का उत्तर तर्क और तकनीकी कसौटियों पर खरा है, लेकिन चीफ-जस्टिस के सवाल के जबाव में एआई वकील का उत्तर उस तकनीक को जानने का आग्रह करता है कि अपराधिक जघन्यता की मात्रा और असाधारणता कैसे निर्धारित होगी ? आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के टूल्स के साथ शुरू इस बहस को अभी तक कोई सिरा नहीं मिल सका है। मनुष्य की संवेदना, सहनशीलता, सृजनता, संस्कारिता, नृशंसता, न्यायपरकता, कठोरता, दया-करूणा, ममता, साधना, वासना जैसी अनगिन मानवीय संवेदनाओं में अंतर्निहित भावावेगों के परिणामों और दुष्परिणामो को निर्धारित करने का कोई वैज्ञानिक टूल अभी तक विकसित नहीं हो पाया है।

मानवीय भावावेगों का आकलन करने में असमर्थ मशीन या औजारों के सहारे समाज में न्याय-अन्याय और उचित-अनुचित के पैमाने निर्धारित करने के खतरों की पहचान करना जरूरी है। सवाल यह है कि समाज के विभिन्न संस्थानों और न्यायालयों में आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के उपयोग को लेकर हमें चिंतित होने की जरूरत है भी या नहीं है...? अथवा हमे कितना चिंतित होना चाहिए...? आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के टूल्स के उपयोग को लेकर दुनिया में अभी भी विभ्रम का धुंध छाया है। यह धारणा अथवा विचार चरमोत्कर्ष पर तैर रहा है कि आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के टूल्स या तो दुनिया को कई मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के मामले में मददगार साबित होंगे अथवा ये मानवता को नष्ट कर देंगे।

लोग एआई टूल्स को दुधारी तलवार की तरह देख रहे हैं। दुनिया और आम आदमी की जिंदगी में आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के अनुप्रयोग निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि एआई टूल्स क्या मानवीय कौशल और अनुभवों के महत्व को शून्य बना देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस सबसे विध्वंसकारी हालिया तकनीकों में शुमार होने लगा है। जबकि कुछ क्षेत्रों मे एआई टूल्स मनुष्यों से बेहतर, त्वरित और तर्कसम्मत परिणाम देने वाले साबित हुए हैं।

एआई एक ऐसा टूल है, जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे, दोनो रूपों में हो सकता है। मुद्दा यह है कि टूल्स का इस्तेमान कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कितना करता है, और इसके आसपास सुरक्षा के उपाय कितने सटीक और प्रभावी किए गए हैं ? फिलवक्त इसके अनुप्रयोग बहुतायत में है, लेकिन सुरक्षा उपाय कम हैं। एआई टूल्स के उपयोग में कुछ परेशानियां तो रूबरू खड़ी महसूस होती हैं। तकनीकी रूप से समर्थ कानूनविज्ञों का कहना है कि पक्षपाती डेटा और एल्गोरिदम न्याय को पक्षपातपूर्ण दिशा की ओर ढकेल सकते हैं। गलत सूचनाओं और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार-प्रसार न्यायिक तंत्र को प्रभावित कर सकता है।

लेकिन अच्छे एआई टूल्स धोखाधड़ी को पहचानने और गलत सूचनाओं को फिल्टर करने में मददगार भी साबित हो सकते हैं। वैज्ञानिक समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के टूल्स की डिजाइन, विकास और नियोजन ऐसा हो कि यह सिर्फ इंसान की बेहतरी के लिये प्रयुक्त हो सके, बुरे प्रभावों को पूरी तरह फिल्टर कर सके।

न्याय प्रणाली में एआई टूल्स पूर्वानुमानित पुलिसिंग, इलेक्ट्रानिक खोज और जांच-पड़ताल में मददगार और साक्ष्य संबंधी मामलो में उपयोगी सिद्ध होते रहे हैं। पिछले साल 25 नवम्बर, 2023 को निवर्तमान चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने 36 वें ''द लॉ एसोसिएशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक सम्मेलन' में आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस की महत्ता को रेखांकित किया था। उन्होने कहा था कि- 'वर्तमान डिजिटल युग में हमे आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के कई दिलचस्प पहलुओं का अलग-अलग तरीकों से सामना करना पड़ रहा है। आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के इस युग में हम इन तकनीकों के नैतिक इस्तेमाल को लेकर कई मौलिक सवालों के रूबरू खड़े हैं।' चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस और मानवीय व्यक्तित्व के बीच एक जटिल अंतर-संबंध है, जहां पर हम खुद को अज्ञात क्षेत्रों में नेवीगेट करता हुआ पाते हैं। आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस से ये अंतर-संबंध और मौजूदा परिस्थितियां मनुष्य के नाते हमसे भिन्नता के साथ एक दार्शनिक प्रतिबिंब और व्यवहारिक विचार, दोनों के अनुसरण की अपेक्षा रखते हैं। इस भिन्नता का खुलासा करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रोबोट सोफिया का खासतौर से उदाहरण दिया, जिसे सऊदी अरब जैसे कट्टर देश ने नागरिकता प्रदान की है।

इसके पूर्व 24 जुलाई, 2023 को आयआयटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुएचीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस के संदर्भ में कहा था कि-'कोई भी तकनीक कभी भी तटस्थ नही होती है'।' वास्तविक दुनिया में लागू होने के बाद ही यह पता चल पाता है कि वह तकनीक मानवीय मूल्यों को कैसे और कितना प्रतिबिंबित कर पा रही है'?'ऐसा इसलिए है कि कोई भी प्रौद्योगिकी सामाजिक शून्यता में विकसित नहीं होती है। ये घटनाक्रम कानूनी, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं औरसामाजिक वास्तविकताओं की एक जटिल टेपेस्ट्री के अंदर घटित होते हैं।' जिम्मेदार लोगों को इन पर अलग तरीके से विचार और विनिमय करना चाहिए।

उन्होने आगाह किया कि एआई टूल्स का उपयोग भेदभाव और अनुचित व्यवहार को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। समाज के निष्पक्ष उपचार को प्रतिकूलताओं की दिशा देने में भी यह महती साबित हो सकता है। डेटा संचालित प्रणालियां पूर्वाग्रहों को कायम रखने का काम भी करती हैं। जैसे कई फर्मों के एआई डिवाइस महिलाओं के बजाय पुरूषों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये डिवाइस सफल पुरूष कर्मचारियों की प्रोफाइल से प्रशिक्षित हैं। यह जेंडर आधारित भेदभाव का जिंदा मिसाल है। एआई टूल्स दुधारी तलवार जैसे होते हैं। जहां तकनीकी में लोगों का जीवन बदलने, सामाजिक विभाजन पाटने और न्याय को सुरक्षित करने की क्षमता है, वहीं नई तकनीक अनपेक्षित व्यवहार को सुविधाजनक बनाने का माद्दा भी रखती है। लोगों के निजी जीवन में तांक-झांक इसका उदाहरण है। नई तकनीकी की उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए मानव व्यवहार को संशोधित करने की जरूरत है।

हमने झारखंड को बनाया है हम ही संवारेंगे: मोदी

पीएम ने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का दिया नारा

● प्रधानमंत्री ने कहा-जब मनमोहन पीएम थे, सोनिया सरकार चलाती थीं ● कहा- कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश,एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे

रांची (एजेंसी)। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बोकारो के चंदनकियारी में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। चंदनकियारी के चंडीपुर मैदान में पीएम ने कहा- भाजपा का यहां एक ही मंत्र है हमने झारखंड बनाया है हम ही संवारेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक रहेंगे, सेफ रहेंगे की बात को भी दोहराया।

● **कांग्रेस-झामुमो जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है-** पीएम मोदी ने कहा कि झामुमो-कांग्रेस ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती हैं। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी-छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दें और अपनी-अपनी जातियों में उलझे रहें। क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज टूट जाए।

● **कश्मीर में धारा 370 के लिए साजिश रच रही कांग्रेस-** जैसे ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दीं। कुछ दिन पहले, उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। क्या देश इसे स्वीकार करेगा।

सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे

पीएम ने कहा- आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरह रहे हैं। इनके (झामुमो) नेता बालू की तस्करी कर करोड़ों कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे। गिनते-गिनते मशीनें भी थक जा रही हैं। ये पैसे कहां से आए। यह आपके हक का नहीं है। यह आपकी जेब से लूटा गया है या नहीं। मैं आपको वादा करता हूं। सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों की कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी जीत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा- वहां की सरकार ने तुरंत बिना खर्ची, बिना पर्ची युवाओं को नौकरी देना शुरू कर दिया है। यहां की सरकार तो खर्ची का मतलब पैसा, पर्ची का मतलब पैरवी समझती हैं। हमारी सरकार आई तो हम यहां भी बिना खर्ची, बिना पर्ची कल्चर को लागू करेंगे। हरियाणा वाले इनके झांसे में नहीं आए। आप लोगों को भी नहीं आना है।

उद्योगों के साथ रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए लगातार जारी है प्रयासः मुख्यमंत्री

आरआईसी और रोड-शो से प्रदेश में बना निवेश के लिये बेहतर वातावरण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास और रोजगार संवर्धन के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर महानगरों में निवेश के लिये हुए रोड-शो से देशभर से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट तक यह क्रम जारी रहेगा। आगामी 7 दिसम्बर को नर्मदापुरम में संभाग स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसमें निवेशकों को नर्मदापुरम क्षेत्र की संभावनाओं से जोड़ते हुए, प्रदेश की आर्थिक बेहतरी के लिए गतिविधियां प्रस्तावित हैं। कॉन्क्लेव में सभी सेक्टर्स के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, भारी उद्योग, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग सहित सभी प्रकार के उद्योग धंधों के माध्यम से राज्य के लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। राज्य सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है म.प्र.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश न सिर्फ औद्योगिक हब बन रहा है बल्कि हर क्षेत्र में उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग अनुकूल नीतियों और मजबूत अधोसंरचना से मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिये इसी माह हम विदेश भी जाने वाले हैं। जहाँ विदेशी उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिये राज्य सरकार की नीतियों और यहाँ के औद्योगिक वातावरण से अवगत करा कर आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि प्रदेश में बेहतर आर्थिक वातावरण बने, लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें, युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप स्थानीय स्तर पर काम मिलें, उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

निवेशकों के लिये उद्योग मित्र नीतियाँ

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि सरकार ने उद्योग क्षेत्र के लिये वर्ष 2024-25 में 4 हजार 190 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। औद्योगिक निवेश को प्रोत्सहन देने के लिये प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश प्रोत्सहन और कस्टमाइज पैकेज जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नये निवेशकों को उद्योग मित्र नीतियों के साथ सरल और सुगम निवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कई जिलों में शुरू भी हो चुके हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इन सेंटर में जिला कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिये पिछले 8 माह में जो प्रयास हुए, उसमें उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं मुंबई, कोयंबटूर, बैंगलुरू और कोलकाता में हुए रोड-शो के साथ हुए इंटरेक्टिव सेशन के काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इनमें विभिन्न सेक्टर्स में 2 लाख 76 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 3 लाख 28 हजार 670 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाएगा। इस वर्ष 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा।

बेरीनाग मस्जिद विवाद ने पकड़ा तूल, विरोध में सड़क पर उतरे हजारों लोग,प्रशासन अलर्ट

पिथौरागढ़ (एजेंसी)। देवभूमि उत्तराखंड के बेरीनाग में मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इसे अवैध निर्माण बताते हुए स्थानीय लोग विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। लोग अवैध निर्माण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से इसको सील करने की मांग कर रहे हैं। बेरीनाग में एक घर में अवैध रूप से मस्जिद संचालित करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल, कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ के बेरीनाग में कथित मस्जिद को लेकर जनता के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहां अवैध निर्माण का स्थानीय जनता और कई हिंदूवादी संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में जीआईसी मैदान में रविवार को विशाल रैली निकाली गई और अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई।

मेनिफेस्टो का दिन, गठबंधनों ने खोला 'पिटारा'

● भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों की 'कर्जमाफी' का वादा ● सत्ता में आने पर महिलाओं को 2100 रुपए महीने की भी गारंटी ● शाह बोले-चुनाव बाद महायुति की पार्टियां मिलकर सीएम चुनेंगी

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्जमाफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना शिंदे-अजित पवार मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है। शाह ने कहा,भाजपा, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन ने अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। चुनाव के बाद गठबंधन के तीनों सहयोगी मुख्यमंत्री पर फैसला लेंगे। अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है।

महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए का घोषणा पत्र,5 गारंटी

महिलाओं को 3 हजार रुपए महीना,बेरोजगारों को 4 हजार,25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

मुंबई (एजेंसी)। महा विकास अघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। एमवीए ने इसे 'महाराष्ट्रनामा' नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा- हम 5 गारंटी दे रहे हैं और यह पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3 हजार रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50 हजार रुपए देंगे, जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। मेनिफेस्टो जारी करने के बाद खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने लाल किताब का इस्तेमाल केवल संदर्भ के लिए किया है। यह संपूर्ण संविधान नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद को भी ऐसी ही एक प्रति दी थी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 30 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 11 नवंबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

बीजेपी का विस्तार होने के साथ ही बढ़ रही बीमारियां

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन का समय बाकी है। इससे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बागियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे फसल बढ़ती है, बीमारियां भी बढती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारी फसलें हैं, जो अच्छे अनाज के साथ-साथ कुछ बीमारियां भी लाती हैं, इसलिए हमें ऐसी बीमार फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना होगा। एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अलग-अलग कारणों से नए लोग आ रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग देना, विचारधारा के बार में बताना और कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश लगातार जारी है।

जजों पर सिर्फ राजनीतिक नहीं, निजी समूहों का भी रहता है दबाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जजों पर सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि निजी हित समूहों का भी दबाव रहता है। उन्होंने यह बात शनिवार को दिए एक इंटरव्यू में कही। सीजेआई चंद्रचूड़ सोमवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीजेआई ने बताया कि निजी हित समूह टीवी न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे जजों पर एक खास तरह का फैसला सुनाने का दबाव बनता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र रहने की कीमत चुकानी पड़ती है, आपको ट्रोल किया जाएगा, आप पर हमले होंगे। न्यायिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर सीजेआई ने कहा कि सिर्फ उन्हीं फैसलों को देखकर स्वतंत्रता का आंकलन नहीं किया जाना चाहिए।

माई लॉर्ड! मुझे बचाइए, मैं कोमा में जा सकता हूं

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की याचिका पर नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से कहा कि वो यासीन मलिक सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल में जरूरी चिकित्सा उपचार मुहैया कराए। जिनके भूख हड़ताल का दावा किया गया है। मलिक को टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने उनकी मेडिकल देखभाल की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र,दिल्ली सरकार व तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी।

बदल रहा है मौसम, बर्फबारी को तरस रहे पहाड़

- नवंबर का पहला हफ्ता बीता, अब तक नहीं शुरू हुई बर्फबारी
- दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर से बर्फ नदारद

नई दिल्ली (एजेंसी)। हर साल नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 से 4000 मीटर के बीच के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का एक दौर शुरू हो जाया करता है। लेकिन उत्तराखंड में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर में इस बार बर्फ का कतरा भी नजर नहीं आ रहा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 4000 मीटर है। यही स्थिति उत्तराखंड में स्थित चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की है। इन क्षेत्रों में तापमान मैदानों जैसा हैं। ये हालात मानसून के बाद होने वाली बारिश कम होने से बने हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, सितंबर के बाद यहां सामान्य से 90 फीसदी बारिश कम हुई है।

इसके चलते तापमान अचानक बढ़ा। यही कारण है कि नवंबर में भी पहाड़ों का यह हिस्सा सूना है। वहीं, उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण के चलते धुंध बढ़ गई है। दिल्ली, सोनीपत, गाजियाबाद, आगरा समेत कई इलाकों में सुबह 7 बजे एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 300 के पार रिकॉर्ड किया गया। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा चल रहा है। ठंड उतनी नहीं पड़ रही है,जितनी इन दिनों में हुआ करती थी।

खाने-पीने की चीजें 60 से 70 फीसदी मिलेंगी सस्ती

- देश के एयरपोर्ट पर अब नहीं पड़ेगी 'महंगाई' की मार
- 200 में मिलने वाली चाय अब मात्र 60 में ले सकेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयरपोर्ट पर खाने-पीने की चीजें किफायती दाम पर भी मिलेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है। यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होगा, जहां यात्री सस्ते में खाने-पीने का सामान खरीद सकेंगे। एएआई के अधिकारियों का कहना है कि इन आउटलेट्स पर खाने-पीने का सामान लगभग 60-70 फीसदी तक सस्ता मिलेगा। अभी एयरपोर्ट पर एक चाय लगभग 125-200 रुपए तक की मिलती है, लेकिन किफायती जोन में यह 50-60 रुपए के बीच मिल सकेगी। हां, इतना जरूर

है कि महंगे रेस्तरां की तरह सर्विस और क्वांटिटी का अंतर होगा। यानी बैठने की जगह स्टैंडिंग टेबल लगी होगी। छोटे कप या गिलास में चाय दी जाएगी। फुल मील की जगह कॉम्पैक्ट मील होगा। पैकिंग की बेसिक क्वालिटी में सामान उपलब्ध होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, लंबे समय से यात्री और हर राज्य के जनप्रतिनिधि शिकायत करते रहे हैं कि एयरपोर्ट पर खाने-पीने का सामान इतना महंगा होता है कि आम यात्री नहीं खरीद पाते। सामान्य यात्रियों को घर से एयरपोर्ट पहुंचने और फिर यात्रा पूरी करके गंतव्य तक पहुंचने में लगभग छह से सात घंटे का औसत समय लगता है। चूंकि एयरपोर्ट और विमान दोनों ही जगह ऐसी हैं जहां यात्री चाय-पानी या भोजन कर सकता है। मगर कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि लोग नहीं ले पाते।

रूस-यूक्रेन का युद्ध रुकवाने ट्रंप का 'पीस प्लान' तैयार!

- यूरोपियन सैनिकों की तैनाती और रूस-यूक्रेन के बीच बफर जोन का है प्रस्ताव

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी चुनावों में जोरदार जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप देश के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर लगातार जो बाइडन और कमला हैरिस को घेरा है।

उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडन की आलोचना करते हुए ये तक कहा कि सत्ता में आने के 24 घंटों के भीतर वह रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप अगले साल जनवरी में जब व्हाइट हाउस लौटेंगे तो उनके सामने इस युद्ध को रुकवाने की चुनौती होगी। हालांकि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने बाकायदा इस संबंध में अपना प्लान तैयार कर लिया है। द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने के लिए रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच 800 मील का बफर जोन तैयार करने का प्लान किया है। इस बफर जोन लागू करने के लिए यूरोपीय सैनिकों को बुलाया जा सकता है। ट्रंप के इस 'पीस प्लान' को उनके तीन कर्मचारियों ने आउटलाइन किया है। ट्रंप के इस प्लान के अनुसार मौजूदा फ्रंट लाइन अपनी जगह पर स्थिर होगी और यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएगा। अमेरिका बफर जोन में गश्त करने और उसे लागू करने के लिए यूक्रेन को मदद नहीं देगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की टीम के एक सदस्य ने कहा, हम यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे।

म.प्र.में एक लाख पदों पर जनवरी से भर्ती

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जनवरी 2025 से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को स्वयं इस कार्य को देखने और समय सीमा के भीतर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा है तो मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।

प्रदेश में इस समय लगभग सात लाख नियमित कर्मचारी हैं। रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण विभाग आउटसोर्स या फिर संविदा कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। इससे काम की गुणवत्ता भी प्रभावित हो

रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने का निर्णय लिया है।

रिक्त पदों की मांगी गई जानकारी- मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को पत्र जारी कर 2024 में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी पूछा है कि अगस्त 2022 तक किस श्रेणी के कितने पदों की भर्ती की गई। परिणाम इनके जारी हुए या नहीं और चयनित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण किया है या नहीं। 31 मार्च 2025 तक कितने पद किस संवर्ग के रिक्त हो जाएंगे।वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर भर्ती के लिए कब स्वीकृति ली गई।

पीडीए मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी

कटेहरी में सीएम योगी ने सपा पर चुन-चुनकर साधा निशाना

अंबेडकरनगर (एजेंसी)। यूपी उपचुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अंबेडकरनगर के कटेहरी विधानसभा में पहुंचे। यहां भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के समर्थन में जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जहां सरकार की योजनाओं का बखान किया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने सपा के पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया।

मंच से संबोधन के दौरान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वह खतरनाक है। इसीलिए हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है। हरियाणा वाले कहते थे बंटे थे इसलिए कटे थे। 2014 के पहले कांग्रेस सरकार थी तो पाकिस्तान घुसपैठ करता था।

एससी-एसटी पर सबसे ज्यादा हमले सपा सरकार में हुए

सीएम ने कहा कि जब हम सरदार पटेल की जयंती मना रहे थे तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। एससी और एसटी समाज पर सबसे ज्यादा हमले सपा सरकार में हुआ। सपा वालों ने एससी-एसटी के छात्रों का स्कालरशिप भी रोक दिया था। हमारी सरकार ने यूपी में 56 लाख गरीबों को मकान दिया है। दो करोड़ 62 लाख गरीबों के घर शौचालय बन गया है। अब 70 वर्ष से ऊपर के लोगो को पांच लाख का इलाज मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर में तीन घंटे में दूसरा एनकाउंटर

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह महज 3 घंटे के अंदर 2 जगहों पर एनकाउंटर चल रहे हैं। पहला श्रीनगर के जबरवान इलाके में और दूसरा किश्तवाड़ के छास में। किश्तवाड़ एनकाउंटर में पैरा स्पेशल फोर्स के 3 जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किश्तवाड़ में कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के आतंकवादी ही छिपे हैं, जिन लोगों ने 2 विलेज गार्ड की हत्या की थी। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच पिछले 18 घंटों के अंदर यह तीसरी मुठभेड़ है। जबकि नवंबर महीने के 10 दिन में यह 8वां एनकाउंटर है। जिनमें अब तक कुल 8 आतंकी मारे गए हैं।

मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड निकला आतंकी पन्नू का करीबी

गिरफ्तारी के बावजूद कनाडा सरकार की हो रही फजीहत

ओटावा (एजेंसी)। कनाडा के हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए हमले के चलते ठंडे पड़े भारत कनाडा रिश्ते पिछले हफ्ते और ज्यादा खराब हो गए थे। कनाडा की लगातार होती फजीहत के बाद कनाडाई पुलिस हमलावरों के खिलाफ एक्शन ले रही है। खबरें हैं कि अब पुलिस ने अब इस केस में चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम इंदरजीत गोसाल है। हिंदू मंदिर में हमले के मामले में गिरफ्तार गोसाल को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी और संदिग्ध हालत में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर के साथ काम करने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर टोरंटो में हिंदू मंदिर पर हमले का प्लान इंदरजीत ने ही तैयार किया था। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि उसे कुछ समय बाद ही छोड़ दिया गया है।

एमपी में नर्सिंग कॉलेजों में थीं 45 हजार सीटें, इस साल 6 हजार से भी कम पर होगा एडमिशन

अब 485 कॉलेजों में से लगभग 350 बंद हो सकते हैं, क्योंकि वे मान्यता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरे

भोपाल (नप्र)। सीबीआई और हाई कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति के परीक्षण में भले ही लगभग 175 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के योग्य पाए गए हैं, पर सख्ती के चलते कई कॉलेज संचालक हाथ खींच रहे हैं। उन्होंने मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं किया है, मान्यता नवीनीकरण के लिए लगभग 300 आवेदन आए थे, जिनमें 125 के करीब ही मान्यता योग्य बताए जा रहे हैं।

सीटों की बात करें तो इन 125 कॉलेजों में जीएनएम (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) और बीएससी (नर्सिंग) मिलाकर लगभग छह हजार सीटें ही हैं, जबकि वर्ष 2020 के बाद एक समय ऐसी स्थिति

थी कि प्रदेश में 670 नर्सिंग कॉलेजों में 45 हजार तक सीटें थीं। यह कॉलेजों और सीटों की अब तक की सर्वाधिक संख्या रही। सीटें कम होने का बड़ा नुकसान नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की तैयारी कर रहे युवक-युवतियों का होगा।

कोई नया कॉलेज नहीं खोला जाएगा- मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों ने बताया कि एक-दो दिन के भीतर मान्यता जारी होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने तय किया है वर्ष 2023 की तरह इस वर्ष भी कोई नया कॉलेज नहीं खोला जाएगा, सिर्फ पहले से संचालित कॉलेजों को ही मान्यता दी जाएगी। नवीनीकरण के लिए कॉलेजों से आवेदन मांगे गए थे, जिनके परीक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है। मान्यता नवीनीकरण सूची जारी होने के बाद एमपी ऑनलाइन से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रवेश के लिए कर्मचारी चयन मंडल पहले ही प्रवेश परीक्षा आयोजित कर चुका है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

बंद हो जाएंगे 350 कॉलेज

बता दें, लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में मापदंड को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कुछ कॉलेजों का फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पकड़ा। हाई कोर्ट ने अपात्र कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए। इस तरह लगभग 200 कॉलेज बंद हो गए। अभी 485 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें लगभग 350 बंद हो जाएंगे क्योंकि वे मान्यता के लिए जरूरी सुविधाओं के पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे। आगे भी यही स्थिति रही तो प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार नर्सिंग कर्मचारी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को नहीं मिल पाएंगे।

इंदौर में दो हफ्ते ज्यादा नहीं सताएगी ठंड

नवंबर का दूसरा हफ्ता भी शुरू से ही गर्म, दिन-रात का तापमान 9 दिनों से सामान्य से ज्यादा

इंदौर। इंदौर में इस बार नवंबर में तेज सर्दी के आसार कम हैं। इसका कारण है कि अभी हवा की दिशा पूर्वी बनी हुई है। इसकी वजह से वातावरण में ठंडक नहीं घुल पा रही है। स्थिति यह है कि नवंबर के 10 दिनों से दिन और रात का तापमान सामान्य से ज्यादा ही बना हुआ है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा की दिशा उत्तरी होने पर एकदम से ठंडापन बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति माह के आखिरी हफ्ते में बन सकती है। तब तक तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा और ठंड बेअसर रहेगी।

सीनियर वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चल रही पूर्वी हवाएं प्रदेश में आती रहेंगी। इससे उत्तरी हवाएं नहीं आएंगी और ठंड का असर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दरअसल उत्तर भारत में बर्फबारी होने के बाद पूरा मध्यप्रदेश ठिठुरने लगता है।

हर साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में उत्तर से ठंडी हवाएं आने लगती है लेकिन वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में पूर्वी हवाओं का जोर है। ये हवाएं मप्र में आई तो उत्तरी हवाओं का जोर ज्यादा नहीं रहेगा। इससे तापमान में ज्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है।

अभी ज्यादा ठंड की संभावना नहीं- इस समय प्रशांत महासागर पर अलनीनो तटस्थ है। इसी प्रकार हिंद महासागर पर तटस्थ डाइपोल की स्थिति रहने की संभावना है। लॉनीना का असर भी नवंबर के आखिरी और दिसंबर में रहने की संभावना है। ऐसे में नवंबर में बहुत ज्यादा सर्दी की संभावना नहीं है। दिसंबर में ही कड़ाके की सर्दी हो सकती है।

अभी दिन रात का तापमान एक जैसा- अभी इंदौर में स्थिति यह है कि ठंड असर नहीं दिखा रही है। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ही हल्का ठंडापन महसूस हो रहा है। तापमान के आंकड़े भी बता रहे हैं कि दिन और रात का तापमान पिछले 10 दिन और रात करीब-करीब एक जैसा ही बना हुआ है। दिन का तापमान 32 तो रात का पारा 18 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हो रहा है।

इस लिहाज से बारिश के बाद ठंड की भी कमजोर शुरुआत हुई है। नवंबर के अगले 5 दिन भी मौसम में बहुत ठंडेपन के आसार नहीं है। दरअसल, हवा की दिशा भी अभी पूर्वी बनी हुई है, जिसकी वजह से ठंडापन वातावरण में नहीं घुल रहा है। हवा की दिशा उत्तरी होने पर एकदम से ठंडापन बढ़ जाएगा।

इंदौर में सरकारी महिला कर्मचारी के घर चोरी

सोने के कंगन और अंगूठी ले भागे ; कपड़ा शोरूम संचालक के मकान में भी घुसे बदमाश

इंदौर। इंदौर में सरकारी महिला कर्मचारी के यहां पर चोरी हो हुई। महिला अपने पैतृक घर पर परिजनों से मिलने गई थी। इसी दौरान बदमाश वारदात को अंजाम देकर चले गया।

सांई पॉम निवासी राशि सोलंकी ने अपनी शिकायत में बताया कि वह शासकीय सेवक है। 7 नवंबर की रात में पति नवनीत सोलंकी के साथ सुदामा नगर अपने पैतृक निवास पर गई थी। शनिवार सुबह पति

के पास पड़ोसी जेके सोनी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि आप घर आ गए क्या? दरवाजा खुला पड़ा है। तब पति ने इंकार किया। हम तुरंत वहां पहुंचे तो बाहर लोहे के गेट का लॉक लगा हुआ मिला। अंदर के दरवाजे का लॉक टूटा था। कमरे में जाकर देखा तो अलमारी से सोने की चेन, दो सोने के कंगन, सोने की अंगूठी अन्य जेवर ले भागे। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी।

इनके यहां भी हुई चोरी की वारदात- प्रमोद पहाड़िया का गृह श्रृंगार के नाम से कपड़े का शोरूम है। उनका रामचंद्र नगर में मकान का निर्माण चल रहा है। यहां पर सरिए, लोहे के गेट, बैटरियां रखी हुई थी। जिसे अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया।

वैभव नगर बिचौली रोड निवासी डॉ. वीरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मोबाइल चोरी को लेकर केस दर्ज किया है। डॉक्टर वीरेंद्र प्रकाश चंद्र सेठी नगर में डॉक्टर है। 30 अक्टूबर को वह चोइथराम मंडी में फूल खरीद रहे थे। तब उनका मोबाइल जेब में रखा था। इस दौरान आरोपी ने उनका मोबाइल चुरा लिया। पुलिस ने मामले में डॉक्टर से लिखित आवेदन लिया था। इसके बाद शनिवार को केस दर्ज किया गया।

इंदौर नारकोटिक्स ने पकड़े गांजा के पौधे

खेती करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ; राजस्थान के तस्करों से जुड़े हैं तार

इंदौर। इंदौर की नारकोटिक्स विंग ने शनिवार गांजा के कटे हुए 400 पौधे बरामद किए हैं, इनकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दबिश के पहले आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसके गिरफ्त में आने के बाद नशे के कारोबार का खुलासा हो सकता है, फ़िलहाल पुलिस तलाश में जुटी है।

हाड़ा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि धार के नजदीक मनावर के गांव बनेड़िया सोलियापुर में गांजा की खेती की जा रही है। हम आरोपी राजा राम केवड़ा के खेत में पहुंचे, तब तक वह भाग चुका था। उसने अपने खेत में लगे गांजा के सभी पौधे काटकर भाई के खेत में कुएं के पास इकट्ठा कर दिए थे।

आगे बताया कि आरोपी राजा राम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि उसके इंदौर और राजस्थान के ड्रग तस्करों से तार जुड़े हुए हैं। वह गांजा की सप्लाई इंदौर के आसपास करता था। उसके पकड़ में आने के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा।

इंदौर में कॉलेज स्टूडेंट को रिश्तेदार ने किया बैड टच

विरोध करने पर बोला- पत्नी से मत कहना झगड़ा होगा ; एक माह बाद केस दर्ज

इंदौर। इंदौर के परदेशीपुरा में एक छात्रा ने छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज कराया है। छात्रा रिश्तेदार के यहां एक साल पहले पढ़ाई के लिए आई थी। करीब एक माह से उसे मौसा अलग-अलग तरीके से बैड टच कर परेशान कर रहा था। मौसा की हरकतों से परेशान होकर मौसी को पूरे मामले में शिकायत की। बाद में मां को कॉल कर बताया। मां के इंदौर आने के बाद शनिवार को मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई।

परदेशीपुरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, निजी कॉलेज से फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही 20 साल की छात्रा की शिकायत पर उसके रिश्तेदार इन्द्रजीत पर छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया है। छात्रा ने शिकायत में बताया कि वह बाहर की रहने वाली है। एक साल से पढ़ाई को लेकर इंदौर में अपने रिश्तेदार के घर आकर रुकी थी।

जब इंदौर आई तब रिश्तेदार इन्द्रजीत उसे बेटा कहकर बुलाते। लेकिन 15 दिनों से उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। उनकी पत्नी घर से बाहर जाती तो कहते कि तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। तुम बहुत अच्छी लगती हो। पहले उनकी बातें समझ नही आई। बाद में पता चला कि इन्द्रजीत बुरी नियत रखते है। जब भी उनकी पत्नी बाहर जाती तो वह गलत तरीके से हाथ पकड़ते, आते जाते अश्लील इशारे कर गलत शब्दों से आवाज लगाते।

बैड टच कर किसी को न बताने की बात कही- छात्रा ने पुलिस को बताया कि 4 दिन पहले की बात है। इन्द्रजीत ऑफिस से जल्दी घर आ गए। आते ही उन्होंने गले लगाया और गाल पर बुरी तरह से बेड टच किया। तब उन्हें धक्का दिया।

पति की मौत के बाद थाने पहुंची डॉक्टर पत्नी

2 दिन बाद पति पर षड्यंत्र तो सास-ससुर और देवर पर प्रताड़ना के आरोप

इंदौर। फरीदाबाद में निजी कंपनी में मेडिकल कंसल्टेंट के पद पर काम कर चुकी हौम्योपथी महिला डॉक्टर ने पति की मौत के दो दिन बाद थाने में शिकायत करते हुए परिजनों पर आरोप लगाए है। उन्होंने देवर,सास और मौसी सास के बेटे पर घर में नही जाने देने और प्रताड़ित करने के मामले में शिकायत की है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पति के मौत के बाद सुनाई आपबीती- द्वारकापुरी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिखा माहेश्वरी निवासी गुमाश्ता नगर ने अपनी सास शशि माहेश्वरी,देवर विनीत और ससुर टीनू पर गंभीर आरोप लगाए है। जिसमें पुलिस ने केस दर्ज किया है। शिकायत में शिखा माहेश्वरी ने बताया कि वह पेशे से हौम्योपैथी डॉक्टर है। पहले निजी कंपनी फरीदाबाद में मेडिकल कंसल्टेंट के पद पर काम कर चुकी है। साल 2022 से वर्क फ्रॉम होम कर रही है। लेकिन पिछले तीन माह से कुछ काम नही कर रही है। शिखा के मुताबिक उनका पहले पति से तलाक हो चुका है; उनकी एक 6 साल की बेटी है। फरवरी 2024 में उनकी पुनीत माहेश्वरी से फेसबुक पर जान पहचान हुई। दोनों में बातचीत के दौरान साथ रहने और शादी करने की बात हुई। 18 जून 2024 में पुनीत,बेटी और वह फरीदाबाद से इंदौर आ गए। पुनीत के ऊपर कर्ज था तो दुकान में सामान भरने को लेकर रूपए मांगे। जिसमें 5 लाख रूपए 28 जून को पुनीत के खाते में ट्रांसफर किये। इसके बाद दोनों लिव इन में कुछ दिन रहे। 9 जुलाई को आर्य समाज में शादी की।

पुलिस ने समझाइश देकर भेज दिया था घर

श्रीलंका से आने के बाद पुनीत ने 6 सितंबर को कहा कि विदेश जाकर गोल्ड का बिजनेस करना है, रूपए नही मिले तो सुसाइड कर लेगा। तब पुनीत को 3 लाख ओर दिए। जो उसने डूबो दिए। पुनीत ब्याज बट्टे का काम करता। सूदखोरी पर रूपए लेता और देता। पुलिस थाने के चक्कर लगा चुका था। यह बात ससुराल में रहते हुए पता चली। मां ने शादी के दिन गोल्ड ज्वेलरी दी। जो 19 अगस्त को अलमारी में चेक किया तो सोने की 10 ग्राम की अंगूठी,देवर को दी गई अंगूठी दोनों नही थी। इस पर तीनों के खिलाफ राजेन्द्र नगर थाने पहुंची। यहां पर शिकायत की। कुछ गोल्ड पुनीत ने यह कहते हुए ले लिया था कि वह जिस केस में फंसे है, उसमें पुलिस कभी भी आकर घर से सोना जब्त कर लेगी इसलिये घर पर रखना सेफ नही है। बाद में गोल्ड टीनू से मांगा तो उसने अपशब्द कहे और घर से भगा दिया। राजेन्द्र नगर पुलिस को की गई शिकायत पर पुलिस ने समझाइश दी।

पत्नी-बच्ची के साथ भी की थी मारपीट

पुनीत ने शादी के दौरान खाने-पीने के रूपए, मंगलसूत्र,अंगूठी का पेमेंट शिखा के अकाउंट से लिया। वही 50 हजार नगदी ट्रांसफर कराए। शादी की रात में पुनीत से रूपए के बारे में जानकारी मांगी तो उसने अप शब्द कहे और वही मारपीट करने लगा। कुछ दिन घर में सामान्य रहे। इसके बाद 12 अगस्त को पुनीत जबरदस्ती श्रीलंका जाने के लिये फोर्स किया। 5 लाख की मांग की। इनकार करने पर सास शशि और देवर विनीत ने पुनीत के अकाउंट में रूपए ट्रांसफर करने के लिये दबाव बनाया। उन्होंने कहां कि रूपए नही दोगे तो बच्ची सहित घर से निकाल देगे। इसमें पुनीत के अकाउंट में 5 लाख 10 हजार का आरटीजीएस कराया। पुनीत ने कहा कि जब वापस इंदौर एअरपोर्ट पर आयेंगे तो पेमेंट वापस कर देगे। पुनीत को जुआ खेलने की आदत थी। उन्होंने श्रीलंका में कैसिनो में काफी रूपए उड़ाए। वह यहां दिए गए सभी रूपए हार गया। इसके बाद छोटी मोटी अकाउंट नगद लेता कभी अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर करवा लेता। रूपए वापस मांगने पर बेटी और मेरे साथ मारपीट की। श्रीलंका जाने के पहले भी बेटी के साथ मारपीट की थी। जिसमें चेहरे पर सूजन आ गई थी।

इंदौर का एमवाए होगा प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल, जहां मिलेगी गोल्फ कार्ट स्ट्रेचर की सुविधा

इंदौर। अब तक हम सरकारी अस्पतालों में देखते थे कि मरीज को स्वजन या अस्पताल के कर्मचारी स्ट्रेचर पर धक्का लगाकर वार्ड में लेकर जाते थे। मगर, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमवाय अस्पताल में अब गोल्फ कार्ट स्ट्रेचर की सुविधा मिलेगी।

इसके लिए अस्पताल प्रबंधन सीएसआर फंड से गोल्फ कार्ट खरीदने की

तैयारी कर रहा है। इस तरह की सुविधा फिलहाल देश के चुनिंदा संस्थानों में ही मरीजों को मिल रही है। इसमें मरीज आराम से लेटकर लिफ्ट तक पहुंचेंगे और उसे वार्ड तक ले जाया जाएगा।

प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में पहली बार ऐसी सुविधा- दावा किया जा रहा है कि यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा, जहां इस तरह की सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी। अधिकारियों ने बताया कि एमवायएच की केजुअल्टी में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं।

यहां इंदौर के अलावा आसपास के जिलों से भी मरीज आते हैं। ऐसे में अब स्ट्रेचर धकाकर मरीजों को लिफ्ट तक और फिर लिफ्ट से वार्ड तक ले जाया जाता है। इसमें समय ज्यादा लग जाता है। लेकिन गोल्फ कार्ट स्ट्रेचर की मदद से मरीजों को पहुंचाने की सुविधा मिलने लगेगी। खास बात यह है कि इस सुविधा को कॉलेज परिसर के अन्य अस्पतालों में भी उपलब्ध कराने की तैयारी है। मगर, यह तभी मिल पाएगी, जब इन अस्पतालों में सड़क निर्माण का काम पूरा हो जाएगा।

गोल्फ कार्ट स्ट्रेचर में क्या-क्या सुविधाएं

यह ई-व्हीकल होगा, जो एक बार चार्ज होने के बाद कई घंटों तक चलेगा। इसमें बोतल टांगने की भी व्यवस्था रहेगी। इसकी मदद से मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकेगा। वहीं, स्वजन को इस स्ट्रेचर को धक्का देने की जरूरत नहीं होगी।

दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए 16 दिसंबर को चलेगी ट्रेन

इंदौर से रवाना होकर तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी का भ्रमण कराएंगे

इंदौर। तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर से रवाना होगी। ट्रेन इंदौर, देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, रानी कमलापति,

इटारसी, बैतूल व नागपुर स्टेशनों से होते हुए जाएगी। 9 रात व 10 दिन की इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।

विद्यासागर स्कूल इंदौर में आयोजन,दो दिवसीय क्षेत्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में 51 स्कूल के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

इंदौर। विद्यासागर स्कूल इंदौर द्वारा 8 और 9 नवंबर को दो दिवसीय सीबीएसई क्षेत्रीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी-2024 की मेजबानी की गई। इस वर्ष की प्रदर्शनी 'सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' विषय पर आधारित थी। इस प्रदर्शनी में सीबीएसई भोपाल क्षेत्र के 51 विद्यालयों ने भाग लिया।

समापन समारोह का शुभारम्भ मां सरस्वती के समक्ष श्लोक वाचन व दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में विद्यासागर स्कूल को सीबीएसई की इस प्रदर्शनी को आयोजित कराने हेतु धन्यवाद देते हुए विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना तथा 'जय विज्ञान जय अनुसंधान' का गुरु मंत्र दिया 7 मेजबान प्रिंसिपल भावना पुजारी ने इस दो दिवसीय आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट

प्रस्तुत करते हुए मुख्य अतिथि, निर्णायकों, विभिन्न सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपलों, सहायक शिक्षकों और प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सीबीएसई को विद्यालय परिसर में दूसरी बार कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि विकास कुमार अग्रवाल क्षेत्रीय निदेशक, सीबीएसई-भोपाल थे। जनक पलटा मैन्लिन विशेष अतिथि थी। इस क्षेत्रीय प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल के सदस्य थे - डॉ. दिलीप वाघेला, डॉ. निहारिका शिवहरे, डॉ. प्रीति शुक्ला, डॉ. पीयूष चौधरी, डॉ. सुल्ताना रजिया, डॉ. उर्मिता शर्मा। यह प्रदर्शनी डिजास्टर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फूड, हेल्थ एंड हाईजीन , मैथेमेटिकल मॉडलिंग आदि आधारित थी। निर्णायकों ने मूल्यांकन पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर सीबीएसई के निर्देशों के आधार पर किया। विद्यासागर स्कूल सहित अन्य चयनित अन्य टीमें आगामी दिनों में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी।

1 करोड़ रुपए का पुरस्कार: इंदौर के पूर्व प्रोफेसर ने की घोषणा

बताना होंगे महाराष्ट्र-झारखंड के चुनाव परिणाम

इंदौर। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और वरिष्ठ शिक्षाविद डॉ पी एन मिश्रा ने महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम बताने वाले को एक करोड़ रुपए का इनाम देने के घोषणा की है।

मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि किसी भी मांत्रिक-तांत्रिक, दरबार लगाने वाले, पर्ची निकालने वाले, पोथी पढ़ने वाले या अपने को सिद्ध पुरुष/सिद्ध माता जी होने का दावा करने वाले को एक करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वह बता सके कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में किस दल को कितनी-कितनी सीटें मिलेंगी।

काउंटिंग से पहले बताना होगा किस दल को कितनी सीट- पी एन मिश्रा ने आगे लिखा है- मतगणना शुरू होने के पहले ही यह बताना होगा कि किस दल को कितनी सीट मिलेगी। अगर कोई यह नहीं

बता पा रहा है तो उसे अपने आपको सिद्ध पुरुष/देवी होने का, तांत्रिक होने का या पर्ची पढ़कर भविष्य बताने का दावा नहीं करना चाहिए।

अपने कर्म और ईश्वरीय विधान पर विश्वास न करके लोग इन लोगों के पीछे घूमते हैं और पाखंड, अंधविश्वास का शिकार होकर अपना समय और धन नष्ट करते हैं। परेशान व्यक्ति इन लोगों के पास इस आशा से जाता है कि उनसे कुछ सहायता मिल जाएगी या वे उसका भविष्य बदल देंगे। भविष्य यदि बदलता है तो वह कर्म से बदलता है।

अनुमान गलत होने पर पाखंड का ढोंग बंद करना होगा- मिश्रा ने आगे लिखा- यदि किसी में दम है तो वह महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों को मतगणना शुरू होने के पहले सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर यह बता दे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। पुरस्कार पाने के लिए उसे अपना उत्तर मेल आईडी पर फोन नंबर सहित भेजना होगा। उत्तर गलत होने पर उस व्यक्ति को क्षमा मांगना होगी और यह कहना होगा कि अब वह इस प्रकार का ढोंग और पाखंड नहीं करेगा/करेगी।

अंधविश्वास मुक्त समाज बनाना असंभव नहीं, सिर्फ कठिन

मिश्रा ने आगे लिखा है की पाखंड और अंधविश्वास की जड़ इतनी गहरी जम चुकी है कि आसानी से भारत को पाखंड मुक्त और अंधविश्वास मुक्त समाज बनाना असंभव नहीं तो कठिन जरूर हो गया है। मैं अपने सारे दोस्तों और संपर्क रखने वालों से निवेदन करूंगा कि वे केवल ईश्वरीय व्यवस्था और अपने कर्म पर विश्वास करें ना कि किसी तांत्रिक, मांत्रिक, पर्ची पढ़ने वाले, रजिस्टर रखने वाले, कुंडली पढ़ने वाले आदि पर भरोसा करें।

मेरे गुरु जी कहते थे कि कोई सिद्ध पुरुष या स्त्री दुकान, मजमा या दरबार नहीं लगाते। वह बहुत गुप्त रहता है। कोई जरूरी नहीं कि वह किसी गुफा में ही रहे। वह किसी आफिस में क्लर्क, किसान, व्यवसायी, अफसर आदि भी हो सकता है। उसे पहचानना असंभव नहीं तो अति कठिन अवश्य है।

संपादकीय

'बंटेंगे तो कटेंगे' पर बंटा एनडीए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित नारे 'कटेंगे तो बंटेंगे' पर भाजपा और सहयोगी दलों का गठबंधन एनडीए ही बंटता नजर आ रहा है। भाजपा और शिवसेना शिंदे के अलावा अन्य दलों को यह नारा रास नहीं आ रहा है। विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व अन्य दल तो इसका विरोध कर रही रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में महायुति के भीतर से भी विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। महायुति के तीसरे घटक और शिंदे सरकार में शामिल राकांपा नेता अजित पवार ने खुलकर इस नारे का विरोध किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 'बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है– सबका साथ सबका विकास।' अजित पवार ने कहा कि दूसरे राज्यों के भाजपा के मुख्यमंत्री तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं। हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग–अलग है। हालांकि शिव सेना शिंदे गुट ने पवार के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पवार इस नारे का मतलब आगे समझेंगे। शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता संजय निरूपम ने योगी के नारे की व्याख्या करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप बिखर जाते हैं, तो कमजोर हो जाते हैं। अगर आप एकजुट रहते हैं, तो मजबूत रहते हैं। 'बंटेंगे तो कटेंगे' ये लाइन बिल्कुल चलेगी। अजित दादा को समझना पड़ेगा। वैसे योगी के इस नारे ने बिहार में एनडीए की घटक और मोदी सरकार में शामिल जद यू भी असहज है। जद यू के एमएलसी गुलाम गौस ने भी इस नारे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को अब इस तरह के नारे की जरूरत नहीं है। हम लोग तो एकजुट हैं। इस नारे की जरूरत उन लोगों को हैं, जिन्हें एक संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब हिन्दू हैं, तो फिर हिन्दू कैसे असुरक्षित हो गए? यह जवाब बीजेपी दे। इसके पहले कांग्रेस व सपा योगी के नारे की तीखी आलोचना कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विशेष रूप से नारे की निंदा करते हुए कहा है कि यह एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में कहा कि योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। योगी साधु के कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वो ही हैं और काटने वाले भी वो ही हैं। दूसरी भाजपा इन आलोचनाओ से बेअसर अपने कटेंगे तो बंटेंगे' अभियान को जारी रखे हुए है। आरएसएस ने भी योगी के इस नारे का अनुमोदन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस नारे को स्वीकार करते हुए इसमें कुछ संशोधन किया। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि 'एक रहेंगे सेफ रहेंगे।' जाहिर योगी के इस नारे में हिंदुओं के जाति के आधार पर न बंटने और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए एक होने का आह्वान है। उसे उम्मीद है कि कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट जिस तरह जाति, सम्प्रदाय के आधार पर बटा, उससे हिंदू एकता को और सीधे तौर पर भाजपा की सत्ता को चोट पहुंची है। पीएम मोदी का चार सौ पार का आह्वान भाजपा के 270 तक सिमट गया। इससे जली भाजपा अब मान रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में इस नारे से अगर सत्ता मिली तो सब माफ है।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

पूंजीवाद चांद सितारों तक

अमेरिका के बड़े उद्योगपति ऐलन मस्क जो स्टारलिंक के मालिक हैं, कि तकनीकी शक्ति और संपदा की कल्पना करना मुझ जैसे आम आदमी की समझ से परे है। स्टारलिंक आज दुनिया में सबसे अधिक सैटेलाइट तकनीक को देने वाली कंपनी है जिसके अंतरिक्ष में लगभग 7 हजार सैटेलाइट स्थापित हैं। इस वर्ष यह कंपनी 1300 सैटेलाइट और स्थापित कर रही है यानि सैटेलाइट की संख्या बढ़कर 20000 के करीब हो जायेगी। उनकी योजना 2031 तक समूचे अंतरिक्ष में या कहा जाये तो सारी दुनिया के ऊपर आसमान में 40 हजार सैटेलाइट स्थापित करने की है। इसका मतलब होगा कि दुनिया के हर देश में उनके दो ढाई सौ सैटेलाइट होंगे और एक प्रकार से दुनिया इन नये तकनीकी 40000 तारों का दर्शन करेगी और उसके प्रभाव की परिधि में होगी। अमेरिका जो सुपर पावर है वह भी ऐलन मस्क के स्टारलिंक के पीछे है। अमेरिका में सरकार के यानि नासा के मुश्किल से 700 सैटेलाइट हैं। भारत में तो मात्र 70 ही सैटेलाइट हैं और उनकी कार्य क्षमता भी अभी सिद्ध होना बकाया है यानि भारत से 100 गुना और अमेरिका से 10 गुना ज्यादा सैटेलाइट स्टारलिंक के पास हैं।

अभी तक हम लोग जब देश के उद्योगपतियों या धनाढ्यों की चर्चा करते हैं तो उनमें अम्बानी प्रथम होते हैं जिनकी संपदा 13 लाख करोड़ के आसपास है और शायद ये रेटिंग एजेंसी के अनुसार दुनिया में उनका तीसरा या चौथा नंबर है। अडानी जो करीब 10 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, वो अभी तक अंबानी से पीछे हैंऔर शायद दुनिया में 7वें या 8वें नंबर पर हैं। बिल गेटस जो कभी दुनिया में पहले नंबर पर थे अभी कुछ नीचे आये हैं और वारेन बफेट भी जिनके पास 70 लाख करोड़ रुपया यानि भारत के सरकारी बजट से लगभग 2 गुना नगदी है अब ऐलन मस्क उनको भी चुनौती देकर पार करने की स्थिति में हैं।

कभी मार्क्स ने पूंजीवादी विकास के क्रम को बताते हुए लिखा था कि बड़ा कारखाना छोटे कारखाने को निगलेगा। पूंजीवाद का सिद्धांत भी यही है कि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। परंतु अब वह पारंपरिक पूंजीवादी ना केवल बहुत नीचे पहुंच जायेगा बल्कि वह सैटेलाइट तकनीक से इन मालिकों की कठपुतली बनेगा। भारत में तो इसका असर दिखना स्पष्ट हो गया है कि भारत के जो दो अमीर माने जाते हैं ये पिछले दिनों याने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से जाकर मिले और उनसे अनुरोध किया है कि स्टारलिंक को भारत के आसमान में याने सैटेलाइट क्षेत्र में मंजूरी ना दी जाये। ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें यह रोक लगाने में यह कहकर असमर्थता व्यक्त की है कि हम तकनीक के विकास और उसके प्रयोग को कैसे रोक सकते हैं। शायद अडानी व अंबानी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं रही होगी और सुना है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में हैं। यह भी संभव है कि सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए उनके और प्रधानमंत्री जी के बीच में अलिखित समझ बनी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी यह जानते हैं कि अगर ये सरकारी स्तर से रोक लगाने का प्रयास करते हैं तो वह असंभव नहीं तो कठिन तो होगा ही। बल्कि उनके लिए वैश्विक स्तर पर नये प्रचार की चुनौती खड़ी करेगा जो उनके निजी भविष्य के साथ-साथ राष्ट्र के भविष्य के लिए भी कुछ चिंतायें निर्मित कर सकता है। यद्यपि अभी मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा।

तकनीक कैसे तकनीक को बाईपास या हजम कर प्रभावी बनाती है यह दुनिया में देखा जा सकता है। एक जमाने में जब लोगों ने पैदल चलना कम किया तो घुड़सवारी शुरू की। युद्ध भी घोड़े पर बैठकर लड़े जाते थे। कहीं-कहीं इन युद्धों में, रथों में या सवारी में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ऊँट और हाथियों का भी प्रयोग किया गया था। फिर कालांतर में विशेषतरू कृषि काल में हाथी, ऊँट व घोड़ों के स्थान पर बैलों का प्रयोग शुरू हुआ और लोगों ने कहीं पर बैलगाड़ियों का और कहीं पर बग्गी के नाम पर भैंसा गाड़ियों का प्रयोग शुरू हुआ और फिर धीरे-धीरे घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, बग्गी आदि सब लुप्त जैसे हो गये तथा गाँव में कृषि के लिए आदमी व बैल के स्थान पर हल बखर आये, फिर हल बखर के बाद ट्रैक्टर आया। इसी प्रकार यात्रा के लिए मोटरसाइकिल, कार और फिर विमान तक पहुंच गये। इसी प्रकार जलयान के लिये, नाव उसके पहले लकड़ी के लटठे, कुट्टीमाटी व नाव फिर पानी के जहाज, अब जलपोत, हवाई जहाज आदि फिर कितने ही प्रकार के उच्चतम गतियों वाले साधन आ चुके हैं। संचार के क्षेत्र में जमीनी फोन आये फिर मोबाइल आये और अब तो एंड्रोइड तकनीक और इंटरनेट ने न केवल उन पुराने टेलीफोन सिस्टम को लगभग समाप्त कर दिया है बल्कि डाकतार विभाग पर भी ताले डलवा दिये हैं। जाहिर है कि जब किसी भी क्षेत्रों में कोई बड़ी तकनीक आती है तो वह न केवल पुरानी तकनीक को खाती है बल्कि उसके माध्यम से रोजगार पाने वालों को भी रोजगार से बाहर करती है। आज गाँवों में 22 करोड़ खेतिहर मजदूरों का स्थान 50-60 लाख ट्रेक्टरों ने या 2-3 लाख हारवेस्टर्स ने ले लिया है। देश के 50 लाख से 1 करोड़ कपड़ा धोने वाले इंसानों का स्थान 10-15 लाख वाशिंग मशीनों ने ले लिया है। अंबानी की चिंता भी यही है कि उनके जिस जियो ने पुराने सभी संचार साधनों को खत्म कर अपना पेट भरा है अब जियो को घरों तक पहुंचाने के लिए सैटेलाइट तकनीक आ रही है। यह सुनिश्चित है कि अंबानी परिवार की संपत्ति धीरूभाई के पेट्रोल पंप की नौकरी की नहीं है बल्कि देश की जनता की सामूहिक पूंजी और मोबाइल और इंटरनेट की कमाई है। और इसी मनमानी कमाई (लूट) के ऊपर उन्होंने अपने थुलथुल बेटे की शादी के दिखावे पर कई हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे और लगभग 100 दिन उनके बेटे का विवाह महोत्सव देश से लेकर दुनिया भर में चला था। जब यह इंटरनेट मोबाइल आया था तो पुराने टेलीफोन वाले रोये थे और जियो मुस्कुराया था। अब जब जियो मरेगा और सैटेलाइट तकनीकी आयेगी तब जियो रोयेगा और उनके समान विक्रेता एयरटेल सुनील भारती आदि लोग भी रोयेंगे तथा स्टारलिंक के सितारे आसमान से मुस्कुरायेंगे। यही है पूंजीवाद जो गाँव-नगर के बाजार से शुरू हुआ और अब चांद सितारों तक पहुंच गया है।

सैटेलाइट तकनीक का एक बड़ा प्रभाव देश और दुनिया में बड़ी रोजगार की आबादी पर भी पड़ेगा। एक अनुमान के आधार पर देश के इंटरनेट और एंड्राइड टेक्नालॉजी के व्यापार में, मोबाइल की दुकान वाले, मोबाइल बनाने वाले, दुनिया की चिप बनाने वाले, मोबाइल सुधारने वाले और ऐसी अन्य सहयोगी काम वाले 40-50 लाख लोग होंगे तो वे अब सब कोई अन्य रोजगार की दुनिया तलाशने को लाचार होंगे। दुनिया की बड़ी-बड़ी चीनी, कोरियाई, वियतनाम आदि की चिप बनाने वाली कंपनियां भी मंदी में जायेंगी क्योंकि सैटेलाइट फोन में कोई चिप नहीं होगी, उसका निर्माण केवल एलन मस्क करेंगे, उसमें न कोई स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, स्पेक्ट्रम के नीलामी में भ्रष्टाचार का मामला भी खत्म होगा और 2जी स्पेक्ट्रम के नाम पर लाखों करोड़ों के घोटाले की चर्चा के आधार पर सरकारों को बदलने वाला भ्रष्टाचार और ईमानदार के पटटे बांटने वाला खेल भी खत्म हो जायेगा।

सैटेलाइट फोन का निर्माण व बिक्री भी केवल एलन मस्क करेंगे, क्योंकि उस फोन रूपी मशीन में जीवन देने वाली क्षमता का सैटेलाइट केवल उन्हीं के पास होगा। अब रोबोट उद्योग पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा और जो बड़ी कंपनियां अभी एआई से चल रही हैं उनको चलाने के लिए आज की तकनीक के मालिक बदल जायेंगे। आज अमेजन कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी है, जिसका मुख्यालय 32 लाख वर्ग फीट जमीन में अमेरिका के सीएटल वाशिंगटन में है और जिसमें 7 हजार रोबोट हैं जो औसतन प्रतिदिन 5 लाख ऑॅर्डर्स की पूर्ति करते हैं। यानि जिस काम में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है उस पर 7 हजार मशीनी मानव काम कर रहे हैं। अमेरिका में अमेजन के वेयरहाउस पर तो लगभग साढ़े 7 करोड़ लाख रोबोट काम कर रहे हैं, जिनमें स्पेरो रोबोट चंद सेकेंड में 20 करोड़ सामनों में से मांगा गया सामान खोज देता है। एआई टनल, चंद मिनटों में खराब सामान छांट देती है और इसी प्रकार से पैकेटस और सीलिंग हो जाती है। रोबिन नाम का रोबोट डिलीवरी करता है यानि सामान को उसके पते पर भेज देता है और जैसे ही कोई पार्सल डिलीवरी बैंक के पास पहुंचता है उसकी लाइट अपने आप जल जाती है और सामान भेज दिया जाता है। यानि अमेजन के वेयरहाउस में 50 लाख लोगों का काम साढ़े 7 लाख मशीनी मानव कर रहे हैं जिन्हें न कोई वेतन, न कोई भत्ता, न भोजन, न पानी चाहिये,केवल बिजली चाहिये।

सैटेलाइट तकनीक का एक बड़ा खतरा राष्ट्रों की सुरक्षा, अंतरविद्रोह और युद्ध में भी होगा। अगर कहीं कोई दंगा फसाद या आपसी संघर्ष होता है और उसके चित्र लोगों को भड़का सकते हैं तो अभी तक सरकारें कुछ समय के लिए इंटरनेट बैन कर उनको दिखाने पर रोक लगाती थी। भले ही यह प्रयोग शत प्रतिशत सही ना हो या कभी-कभी सरकारें इन आविष्कार का दुरुपयोग करती है, पर कुछ तो फर्क पड़ ही जाता था। परंतु अब सरकारें केवल एलन मस्क के ऊपर निर्भर करेंगी क्योंकि सैटेलाइट को रोकना अब देशी सत्ता, देशी तकनीक, देशी उद्योगपति किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा। युद्ध के बारे में भी ऐसी ही स्थितियां हो सकती हैं और एक छोटा सा भले ही झूठा समाचार क्यों न हो परंतु अगर वह जारी हो गया तो वह दुनिया को युद्ध में झोंक देगा।

बहुत संभव है कि कुछ समय पश्चात सैटेलाइट तकनीक का उपयोग युद्धों में हो और परमाणु अस्त्रों-शस्त्रों का उपयोग भी सैटेलाइट तकनीक के पास में पहुंच जाये। पेजर के माध्यम से सैकड़ों कि.मी. दूर बैठे व्यक्ति को उसके हाथ में लिए हुए मोबाइल में विस्फोट कर मारा जा सकता है तो वह दिन दूर नहीं जब सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाना संभव होगा। अभी तक अमेरिका सुपर पावर या अमेरिकी स्टेट सुपर पावर थी परंतु अब सैटेलाइट तकनीक यूएस स्टेट को भी नियंत्रित करने वाली सुपर पावर होगी। राष्ट्र राज्यों की सामरिक शक्तियां एक सैटेलाइट की किरण से छिन जायेगी।

जो लोग गांधी को गाली देने में, दुष्प्रचार करने में अपने जीवन की सफलता मानते हैं, जो लोग लोहिया की उपेक्षा में अपनी सफलता मानते हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए कि उनके ये छुद्र प्रयास दुनिया को नहीं बचा सकते। दुनिया को जो विचार बचायेगा वह गाँधी और लोहिया का विचार होगा।

राजनीति

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

धारा 370 की बहाली से ताकतवर होंगे अलगाववादी

इसे देश का दुर्भाग्य की कहा जाएगा कि जम्मू-कश्मीर में जिस अलगाव और आतंकवाद का पर्याय धारा-370 और 35-ए बनी थीं, उनकी पुनर्बहाली की मांग विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर सत्तारुढ़ दल ने की है। इसका समर्थन कांग्रेस और पीडीपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने किया है। हालांकि भाजपा विधायकों ने विधानसभा में इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए इसे अवैध करार दिया है। इन विधायकों ने सदन में अनुच्छेद-370 और 35-ए को बहाल करने का बैनर लिए गर्भग्रह में पहुंचे अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद के हाथ से बैनर छीनकर फाड़ दिया और नारा लगाया, 'बलिदान हुए जहां मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है।' वहीं नेशनल काफ्रेंस के विधायकों ने नारा लगाया, 'जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कष्मीर हमारा है।' साफ है, कष्मीर में लोकतंत्र की बहाली के बावजूद वहां के बहुसंख्यक आबादी का नेतृत्व करने वाले दल और कांग्रेस संसद और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने से बाज नहीं आ रहे है। जबकि वे जानते हैं कि इन अनुच्छेदों की बहाली अब किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कह रहे है कि दुनिया की कोई भी ताकत इन अनुच्छेदों को बहाल नहीं करा सकती है।

इस प्रस्ताव को लाकर सत्तारूढ़ दल ने पृथकतावादी शक्तियों को हवा देने का काम किया है। महबूबा जहां राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को नकार रही हैं, वहीं फारूख अब्दुल्ला चीन की मदद से अनुच्छेद-370 की वापसी की मांग करके अपनी सांप्रदायिक भावना जता चुके हैं। साफ है, घाटी में खत्म हो चुकी आतंक की फसल के बीज फिर से बौने की तैयारी निर्वाचित सरकार के अस्तित्व में आने के साथ ही शुरू हो गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों विभाजनकारी अनुच्छेदों को शून्य करने के संसदीय फैसले पर मोहर लगा चुकी है। साफ है, यह निर्णय संविधान सम्मत है। दरअसल भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर को भारत सरकार से मिलने वाले धन को न केवल लूटा है, बल्कि लद्दाख और जम्मू क्षेत्र के विकास की भी कभी परवाह नहीं की। इस लूट को पाने के लिए महबूबा और अब्दुल्ला ने परस्पर विरोधी क्षेत्रीय दलों से जो गठबंधन किया है, वैसी मंषा इन नेताओं ने सत्तारूढ़ रहते हुए विस्थापित कष्मीरी पंडितों के प्रति कभी नहीं जताई। अब वे इस लड़ाई को धारा-370 की वापसी का संघर्ष बताते हुए सांप्रदायिक रंग देने में भी लग गए हैं।

धारा-370 और 35-ए के खत्म होने का प्रस्ताव संसद से पारित होने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर का विभाजन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में हो चुका है। अब यहां अलग-अलग राज्यपालों की निगरानी में शासन-प्रशासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कामयाबी के साथ बहाल कर रहा है। इसी क्रम में अलग प्रधान, निशान और विधान का शासन खत्म हो गया। नतीजतन अब सही मायनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को भारतीय संविधान के कानूनी धागे में पिरो दिया है।

अब यहां आधार कार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुस्लिम विवाह विच्छेद, शत्रु संपत्ति कानून, मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, व्हिसल ब्लोअर समेत 108 केंद्रीय कानून अस्तित्व में आ गए हैं। साथ ही इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जो 164 कानून यहां के लोगों को विशेष लाभ देते थे, वे रद्द हो गए हैं। इस राज्य के पुराने कानूनों में से 166 कानून ही नए केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। जो अधिकार देश की दूसरी ग्राम पंचायतों को प्राप्त थे, वे यहां लागू नहीं थे, जो अब लागू हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को मिलने वाला आरक्षण लागू नहीं था, लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत ये

संवैधानिक प्रावधान प्रभावशील हो गए हैं। यहां सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि यहां की आधिकारिक भाषा उर्दु की जगह हिंदी ने ले ली है।

जम्मू-कष्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां आधिकारिक भाषा उर्दु थी। साफ है, इस पूरे क्षेत्र में जो भी देश की अखंडता के एवं भारतीय संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पक्षधर लोग हैं, उन्हें बरगलाना मुश्किल है, क्योंकि कश्मीरी अवाम जान गई है कि इन दोनों परिवारों ने कश्मीर को अपने निजी हितों के लिए न केवल लूटा, बल्कि आतंक की आग में भी झोंक दिया। दरअसल फारूख और महबूबा आज भी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, जो देश विभाजन के समय सामंतों की थी।

धारा 35-ए को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेतृत्व कर्ताओं की विडंबना रही है कि वे एक ओर तो 35-ए का समर्थन करते हैं, जबकि वे भली-भांति जानते हैं कि यह अनुच्छेद आखिरकार भारतीय संविधान का ही हिस्सा है, जम्मू-कश्मीर के विधान का हिस्सा नहीं है, जिसकी पुनर्बहाली के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया है। इसे कश्मीर की आजादी के कथित पैरोकारों का दोगलापन ही कहा जाएगा कि वे भारतीय संविधान का तो बहिष्कार करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इसी में दर्ज प्रावधानों में बदलाव की पहल होती है तो उसका विरोध करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि केवल 35-ए की वजह से कश्मीर में बंटवारे के समय जो लोग आकर बसे हैं, उन्हें 70 साल बाद भी न तो राज्य की नागरिकता मिली थी और न ही भारत की। 1947 में पश्चिमी-पाकिस्तान से पलायन करके जो हिंदु, बौद्ध, सिख और अहमदिया मुस्लिम बसे हैं, वे 35-ए के विलोपीकरण के पहले तक शरणार्थी की हैसियत से रह रहे है। इन परिवारों की संख्या 5764 है। चूंकि इन्हें कोई नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, इसलिए वे न तो किसी भी चुनाव में वोट डाल सकते थे और न ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, उनके बच्चे शैक्षिक छात्रवृत्ति से भी वंचित थे। ये व्यावसायिक शिक्षा देने वाले संस्थानों में भी नहीं पढ़ सकते थे। यह धारा महिलाओं के साथ अन्याय का कारण भी बनी हुई थी। यदि जम्मू-कष्मीर की कोई लड़की इस राज्य के बाहर के लड़के से शादी कर लेती थी तो वह स्वतः ही परिवार के संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाती है। यही हश्र उसके बच्चों का होता था। जो कांग्रेस और राहुल गांधी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें 70 साल तक संवैधानिक अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रखे गए ये पीड़ित समुदाय दिखाई नहीं देते ?

जम्मू-कश्मीर का करीब 60 प्रतिशत क्षेत्र लद्दाख में है। इसी क्षेत्र में लेह आता है, जो अब लद्दाख की राजधानी। यह क्षेत्र पाकिस्तान और चीन की सीमाएं साझा करता हैं। बीते सत्तर साल से लद्दाख कश्मीर के शासकों की बदनीयती का शिकार होता रहा है। अब तक यहां विधानसभा की मात्र चार सीटें थी, इसलिए राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास को कोई तरजीह नहीं देती थी। लिहाजा आजादी के बाद से ही इस क्षेत्र के लोगों में केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चिंगारी सुलग रही थी। 70 साल बाद इस मांग की पूर्ति हो हुई है। इस मांग के लिए 1989 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोषिएषन का गठन हुआ और तभी से यह संस्था कश्मीर से अलग होने का आंदोलन छेड़े हुए थी। 2002 में लद्दाख यूनियन टेरेटरी फ्रंट के अस्तित्व में आने के बाद इस मांग ने राजनीतिक रूप ले लिया था। 2005 में इस फ्रंट ने लेह हिल डवलपमेंट काउंसिल की 26 में से 24 सीटें जीत ली थीं। इस सफलता के बाद इसने पीछे मुडकर नहीं देखा। इसी मुद्दे के आधार पर 2004 में थुप्स्तन छिवांग सांसद बने। 2014 में छिवांग भाजपा उम्मीदवार के रूप में लद्दाख से फिर सांसद बने। 2019 में भाजपा ने लद्दाख से जमयांग सेरिंग नामग्याल को उम्मीदवार बनाया और वे जीत भी गए। लेह-लद्दाख क्षेत्र अपनी विशम हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण साल में छह माह लगभग बंद रहता है। सड़क मार्गो व पुलों का विकास नहीं होने के कारण यहां के लोग अपने ही क्षेत्र में सिमटकर रह जाते हैं। यह वही लद्दाख है, जिसे चीन हथियाना चाहता है, इसी चीन से फारूख अब्दुल्ला कष्मीर की पुरानी स्थिति को बहाल करने की गुहार लगा चुके हैं। हालांकि अब चीन के साथ भारत के संबंधों में कुछ नरमाई आई है और लद्दाख और चीन के बीच स्थित सीमा से दोनों देषों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। हैरानी है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो समझौता हो रहा है, लेकिन जो कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा है, उसे एक बार फिर उमर अब्दुल्ला सरकार अलगाववादियों को सौंपने की तैयारी में लग गई है।

राजनीतिक दशा-दिशा तय करेंगे परिणाम

महाराष्ट्र-उप्र में चुनाव

अनिल ठाकुर

लेखक स्तंभकार हैं।

2024 लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव , हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहे है , क्योंकि ये नतीजे 2029 तक राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। हरियाणा चुनाव नतीजे धारणा के विपरीत आने से एक बार फिर यह उलझन बढ़ गई है कि मतदाता किसी नरेटिव के आधार पर वोट करते है या समयानुसार अपनी धारणाएं बदलते रहते है। कर्नाटक से लेकर हरियाणा चुनावों तक मतदाता ने हर बार चौंकाया है। इसलिए कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि नतीजे किस के पक्ष में आयेगे। एक पक्ष संविधान और आरक्षण तो दूसरा बटने , कटने की दुहाई देकर अपना अपना पक्ष मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए है। दोनो पक्षों में तीन तीन दल है और उनके बीच के अंदुरूनी मतभेद भी जग जाहिर है। महा आघाड़ी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना (उद्धव) और कांग्रेस के बीच की लड़ाई में दोनों दल एक दूसरे को कितनी मदद करेंगे यह शंका पैदा करता है तो महायुति में अजित पंवार की भूमिका को लेकर संशय बना हुआ है। अजीत पंवार ने तो योगी का विरोध कर महायुति के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। महा आघाड़ी में दूसरा साथी दल सीटों में इतना आगे ना निकल जाए कि मुख्यमंत्री पद पर अपना हक जमाने लग जाए इसकी चिंता है तो महायुति में अजित पंवार को लेकर शंकाए है। महाराष्ट्र में बागी दोनों गठबंधनों के लिए मुसीबत बने हुए है , महायुति के लिए थोड़े ज्यादा। ओवैसी और अखिलेश नुकसान तो महा आघाड़ी का करेंगे , लेकिन जरूरत पड़ने पर समर्थन भी उसी का करेंगे। महायुति के लिए राज ठाकरे की स्थिति भी इसी तरह की है। इतनी भुलभुलैया के साथ गारंटी, वारंटी, माफी , नगदी , खटाखट के पांसे दोनों पक्ष फेक चुके है, जनता किसे उपकृत करेगी कहना मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के वादों को पूरा करने में बजट का ध्यान रखने वाले बयान ने कांग्रेस के लिए समस्या पैदा कर दी थी , लेकिन राहुल ने उसे नजरअंदाज करते हुए फिर खटाखट योजना घोषित कर दी। वे जानते है कि खरगे को कर्नाटक की जनता भी नहीं सुनती तो महाराष्ट्र में उनकी कौन सुनेगा। यह चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए जीवन मरण का प्रश्न है , असली नकली शिवसेना के फैसले पर उनका भविष्य टीका हुआ है। अजीत पंवार के लिए आगे पीछे शरद पंवार की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नजर नहीं आता। महायुति जीतती है तो शिंदे के मुख्यमंत्री बने रहने में कोई शंका दिखाई नहीं देती, विपरित नतीजे आने के पर भी उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वजूद तो बना ही लिया है , उनकी अनदेखी करना मुश्किल होगा।

महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति इतनी गड़मगड्ड है कि कहना मुश्किल है कौन सा फैक्टर चलेगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां तीनों राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एवं क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना (दोनों धड़े) सभी करीब करीब समान रूप से मजबूत है। यूपी में अब सीधी लड़ाई अखिलेश के पीडीए और बुलडोजर बाबा के बंटेंगे तो कटेंगे के बीच है। यहां भी टक्कर कांटे की है। योगी के लिए आगे की राह कैसी होगी ये नतीजे तय करेंगे। महाराष्ट्र के नतीजे राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और मोदी सरकार के स्थायित्व भी तय करेंगे। केंद्र में जेडीयू और तेलगु दशम अपनी अगली रणनीति इन्हीं नतीजों के आधार पर तय करेंगे।

इस आधार पर यह माना जा सकता है कि इन दोनों राज्यों के नतीजे 2029 तक देश की राजनीति दशा और दिशा तय कर देंगे।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

प्रदीप मिश्र

लेखक व्यंग्यकार हैं।

त्रेता युग की शुरुआत !...सौगात देने की औकात?

पांच सौ साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या से त्रेता युग का शुभारंभ हो चुका है। राम अपने धाम आ गए। स्वागत और सत्कार के लिए संस्कारवश सत्ता पक्ष के नेता ही बुलाए गए। 22 जनवरी को नए युग का शिलान्यास हुआ था। दिव्य, भव्य और नव्य अयोध्या में अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय दिवाली मनाई। उत्साह, उल्लास, उमंग और तरंग में कुछ भक्तों ने परलोक गमन से पहले ही स्वर्ग की अनुभूति बताई। 25.12 लाख दीपक जलाए गए। रिकॉर्ड बनाए गए। अब बंटेंगे तो कटेंगे का प्रबोधन और उद्बोधन तय हो गया है। चुनाव में मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने तक संबोधन में संशोधन नहीं करने का समय हो गया है। 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मनमौजी ने कंपकपाती उंगलियां दिखाकर एक रहने-सेफ रहने का मंत्र दिया। लौह महिला इंदिरा गांधी का लहू नजरअंदाज कर बताया कि वल्लभ भाई पटेल ने लोकतंत्र दिया। एक जैसी सोच वालों के सुर समान हैं। आंख दिखाने-डराने को मानते स्वाभिमान हैं। सिलिंडर की मंहगाई के तोहफे पर बात नहीं करेंगे। पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटने पर घात नहीं करेंगे। देखते रहिए। दिवाली के बाद दिवाले निकलेंगे। बड़े-बड़े घोटाले निकलेंगे।

त्रेता युग के शुभागमन से पहले जनता जनार्दन को सौगात देने के काम बढ़ गए। शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थरों में नाम बढ़ गए। अब सब राम के नाम से होगा, कोई और बात नहीं होगी। किसी की भी खास औकात नहीं होगी। पड़ोसियों से बेवजह बात नहीं होगी। असंतुष्टों से मुलाकात नहीं होगी। खड़ाऊं से शासन पहले से चल रहा है। इशारों भर से ही प्रशासन मचल-उछल रहा है। केवल नीति की बात होगी। कसम से कहते हैं, राजनीति नहीं होगी। लेकिन एक बात अहम है। इस पर किसी को भी नहीं वहम है। रामलला अभी बालक हैं। इसलिए उनके कई-कई संचालक-परिचालक हैं। ये सब रणनीति और कूटनीति के प्रणेता हैं। इनके ठीक पीछे नेता हैं। नेता से ज्यादातर नाता सिर्फ देने का है। अपने ही टैक्स से सरकार से कृपा के रूप में सौगात लेने का है। सौगात और रेवड़ी नेता घर-घर बांट रहे हैं। एक को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से काट रहे हैं। इसी दौर में कुछ दिन सर्दी, कोहरा, धुंध, स्मॉग, फॉग, तापमान, कपड़ों का दान चलेगा। मीडिया में लारेंस विश्नोई और सलमान खान चलेगा। जैसे ही इसमें हिंदू-मुसलमान हुआ। संवेदनशील मुद्दे को सभी ने चिकोटी की तरह छुआ। दरअसल, हर साल दशहरे से भाषणों में बुराइयों और असत्य का अंत शुरू हो जाता है। आह्वान पर दिखावे-बहकावे-उकसावे का अमल तुरंत शुरू हो जाता है। फिर कहा जाता है कि दिवाली पर पटाखे मत जलाइए। सीधे नहीं कहते, दिमाग लगाइए और प्रतिद्वंद्वी का दिल जलाइए। वैसे भी हैसियत से अधिक खरीदारी, सजावट, गिफ्ट के बहाने किसी न किसी का दिल ही तोड़ा जाता है। पैसा और पावर काप्रदर्शन कर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ा जाता है। कुछ कहते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए मत कीजिए आतिशबाजी। मन करे तो इसी विषय पर खूब कीजिए लफ्फाजी। सोच लीजिए, समझ लीजिए, जल्दबाजी नहीं है। मातहतों का अपमान, सुरापान और मांसाहार संग दांव लगाना जुएबाजी नहीं है। वातावरण में प्रदूषण हर समय रहता है। जानकारों को भी सर्दी-गर्मी के इस खर-दूषण पर विस्मय रहता है। सनातन प्रेमी और विरोधी इसी दौर में ज्यादा सक्रिय होते हैं। दोनों अपने-अपने धड़ों में लोकप्रिय होते हैं। फिर भी सच नहीं बोलेंगे। सचमुच नहीं बोलेंगे।

फेस्टिवल का सीजन निकल गया है। बाजार, कारोबार, मिलावट, सजावट, दिखावट, बनावट का रीजन निकल गया है। जनगणना के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय बताने की तैयारी करिए। इन्हीं मसलों पर ज्यादा जिएं फिर जल्द मरिए। आने वाले दिनों में प्रदूषण और पर्यावरण पर काम किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब की सरकार को बदनाम किया जाएगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छोड़ा नही जाएगा। बेवजह छेड़ा नही जाएगा। दिल्ली में आने वाला विधानसभा चुनाव है। बाकी प्रदेशों में अपना प्रभाव है। जैसा कि इनका और उनका स्वभाव है। आपस में ही बनाना पड़ेगा दबाव है। आप की किस्मत, क्या मिल पाता है। पराली, आग, स्मॉग, भागमभाग और आरोपों के दाग से तो इनका पुराना नाता है। अब स्वदेशी के लिए भी आंदोलन चलाया जाएगा। चीन से संबंध सुधारने के लिए आयात-निर्यात के आंकड़ों के भारी अंतर को भुलाया-छिपाया जाएगा।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

ऐतिहासिक फैसला-1

निजी संपत्ति को लेकर यह फैसला मील का पत्थर

सभी निजी संपत्तियों को राज्य के अधिग्रहण के लिए समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं कहा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में कुल तीन फैसले लिखे गए। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ छह अन्य न्यायाधीशों के साथ बहुमत की अगुवाई कर रहे थे। न्यायमूर्ति नागरत्ना आंशिक रूप से बहुमत से सहमत भी है। न्यायमूर्ति धूलिया इस फैसले से असहमत थे। इसे विचारधारा का बदलाव भी कहा जा सकता है। लेकिन दो न्यायाधीशों ने अन्य बहुमत के फैसले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर पर जो टिप्पणी की गई है उसकी आलोचना भी की।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि सभी निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति सुधांषु धूलिया, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति राजेष बिंदल, न्यायमूर्ति सतीष चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने नेतृत्व में अधिकांश न्यायाधीशों ने कहा कि हमारा मानना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन को केवल एक समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता। क्योंकि, यह भौतिक जरूरतों की योग्यता को पूरा करता है।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, इसे पहले कुछ परीक्षणों को पूरा करना होगा।

न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन संसाधन के बारे में जांच अनुच्छेद 39 (बी) के तहत आती है। संसाधन की प्रकृति, विशेषताओं, समुदाय के कल्याण पर संसाधन के प्रभाव, संसाधन की कमी और ऐसे संसाधन के निजी खिलाड़ियों के हाथों में केंद्रित होने के परिणाम जैसे कारकों की एक गैर-विस्तृत सूची के अधीन होनी चाहिए। विकसित सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत उन संसाधनों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है जो एक समुदाय के भौतिक संसाधन के दायरे में आते हैं। अपना फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि उन्होंने कुछ मुद्दों पर सीजेआई के नेतृत्व वाले बहुमत से सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति धूलिया के फैसले के जवाब में कुछ राय लिखी है। निजी स्वामित्व वाले भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण वितरण के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों में कैसे बदल जाता है जो आम भलाई के लिए सबसे अच्छा है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि यही मेरे फैसले का सार है।

न्यायमूर्ति धूलिया ने अपनी असहमति में कहा कि यह देखना संसद का विशेषाधिकार है कि भौतिक संसाधनों को कैसे नियंत्रित और वितरित किया जाए। निजी स्वामित्व वाले संसाधन क्या और कब भौतिक संसाधनों की परिभाषा के भीतर आते हैं, यह इस न्यायालय को घोषित नहीं करना है। यह आवश्यक भी नहीं है। मुख्य कारक यह है कि क्या ऐसे संसाधन आम भलाई के लिए सहायक होंगे। स्पष्ट रूप से प्रत्येक निजी स्वामित्व वाले संसाधन का अधिग्रहण, स्वामित्व या यहां तक कि नियंत्रण भी आम भलाई को कम नहीं करेगा। फिर भी इस स्तर पर हम क्या करें और क्या न करें की सूची नहीं बना सकते हैं। हमें इस कवायद को विधायिकाओं के विवेक पर छोड़ना चाहिए। वर्तमान मामले में संदर्भ सन् 1978 में शीर्ष अदालत द्वारा सड़क परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से संबंधित मामलों में लिए गए दो परस्पर विरोधी विचारों के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 सी से संबंधित है, जो संविधान के खंड चार में निर्धारित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित कानूनों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 31 सी को 1971 में संविधान के 25 वें संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसने अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट डीपीएसपी को सुरक्षित करने का काम किया। 25 वें संशोधन को प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि संविधान की एक बुनियादी संरचना है जिसे संशोधनों के माध्यम से बदला नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 31 सी को बाद में आपातकाल के दौरान अधिनियमित संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। ताकि सभी डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जा सके, न कि केवल अनुच्छेद 39 (बी) के तहत और 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 42वें संशोधन के खंडों को निरस्त कर दिया, जिसने अनुच्छेद 31 में परिवर्तन को प्रभावी बनाया। उस फैसले के मद्देनजर, वर्तमान पीठ के समक्ष यह सवाल उठाया गया था कि क्या मिनर्वा मिल्स में न्यायालय ने केशवानंद भारती के बाद की स्थिति को बहाल किया या अनुच्छेद 31 सी को पूरी तरह से निरस्त कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ इस पर सहमत थी कि केशवानंद भारती द्वारा बरकरार रखा गया अनुच्छेद 31 सी लागू है। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि केशवंद भारती में जिस हद तक अनुच्छेद 31 सी को बरकरार रखा गया है, वह लागू है और यह सर्वसम्मत है। न्यायालय ने समझाया कि जब कुछ पाठ को कुछ वैकल्पिक पाठ के साथ प्रतिस्थापित करने वाला संशोधन अमान्य हो जाता है, तो प्रभाव यह होता है कि असंशोधित पाठ लागू रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामलों में निरसन और अधिनियमन का विधायी इरादा समग्र है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के बजाय निरसन को प्रभावी बनाने के परिणामस्वरूप एक ऐसा परिणाम होगा जो विधायी परिणाम के साथ सह-संबंधित नहीं है।

क्या प्रकरण है मिनर्वा मिल का

मिनर्वा मिल बेंगलुरू शहर के पास स्थित एक कपड़ा मिल थी। वर्ष 1970 में, केंद्र सरकार ने मिनर्वा मिल्स के उत्पादन (प्रोडक्शन) में भारी गिरावट को देखते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951 की धारा 15 के तहत एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने अक्टूबर 1971 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी। केंद्र सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड को अधिकृत (ऑथराइज) किया जो कि मिनर्वा मिल्स के प्रबंधन को संभालने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951 के तहत गठित एक बॉडी थी। संविधान के संशोधन 39वें में राष्ट्रीयकरण को 9 शेड्यूल में शामिल किया गया। यह न्यायिक पूर्नविलोकन के दायरे से बाहर था। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण में सुप्रीम शक्ति प्राप्त करने के लिए, पार्लियामेंट में संविधान में 42वां अमेंडमेंट पास किया गया था। इसमें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 4 के माध्यम से आर्टिकल 31 सी में संशोधन किया गया था। आगे, 42वें संविधान संषोधन अधिनियम, 1976 की धारा 55 ने आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने धारा 5 (बी), 19 (3), 21, 25 और 27 (राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1974 की 2 अनुसूची के साथ पढ़ा जायेगा) की वैधता को चुनौती दी थी। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 4 और 55 तथा मिनर्वा मील का राष्ट्रीयकरण करने के केंद्र सरकार के आदेष को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अनुच्छेद 31 सी और 368 के तहत 42वें अमेंडमेंट एक्ट, 1976 की धारा 4 और 55 के तहत किए गए सम्मिलन (इन्सर्शन) से मूल ढांचा सिद्धांत में बाधा आती है? क्या भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार पर राज्य की नीति में नीति निर्देशक की प्रधानता है?

याचिकाकर्ताओं की ओर से उनका प्रतिनिधित्व विख्यात अभिभाषक नानी पालकीवाला द्वारा किया गया था। वह जनता सरकार के एम्बेसडर भी थे। जल्द ही उन्हें मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत लौटने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए उन्होंने मिनर्वा मिल्स के पूर्व मालिकों की ओर से मामले में बहस की। संसद की संशोधन शक्तियां आर्टिकल 368 के तहत सीमित है। यह संशोधन संसद को संविधान का निर्माता बनने की अनुमति देगा। केशवानंद भारती मामले में कोर्ट के फैसले ने उल्लेख किया कि संसद को संविधान के बेसिक फीचर को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पर कानून पास करना, स्टेट का दायित्व था। लेकिन, इसे स्वीकृत तरीकों से किया जाना चाहिए। यह मूलभूत अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन एक्ट, 1976 की धारा 55 के कारण किसी भी कोर्ट को संसद द्वारा पारित संविधान संषोधन को पूर्णविलोकन की शक्ति नहीं होगी। इससे न्यायिक और संसद के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा। मूलभूत अधिकार और नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीति के बीच एक असंतुलन पैदा होगा। इसलिए एक मध्यम रास्ता निकालने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा बनाए गए लगभग हर कानून किसी न किसी तरह से नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को बल देने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल एलएन सिन्हा और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.के. वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 सी ने मूल ढांचे के सिद्धांत को मजबूत किया। नीति निदेशक सिद्धांतों ने मूलभूत अधिकारों के अभाव में लक्ष्य प्रदान किया। मूलभूत अधिकारों को होने वाली कोई भी क्षति, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगी। राज्य की नीति निदेषक नीति के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पार्लियामेंट की शक्तियां सर्वोच्च होनी चाहिए। इसकी संशोधन शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक रूचि से जुड़े मुद्दे पर कोर्ट का फैसला नहीं लेना चाहिए। सरकार राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को ऋण जुटाने में सहायता कर रही थी। 31 जुलाई 1980 को, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि 42वें संषोधन अधिनियम, 1976 की धारा 4 और 55 असंवैधानिक है। धारा 5(बी), 19(3), 21, 25 और 27 (राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1974 के 2 अनुसूची के साथ पढ़ा जायेगा) की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

जन जीवन

प्रो. डॉ. वत्सला

(लेखिका और शिक्षाविद)

कुटिया में जीवन का आशय प्रकृति से नजदीकी

कुटिया शब्द बहुत ही विस्तृत फलक वाला है। कुटिया का अर्थ होता है साधु-संतों की झोपड़ी (पर्णशाला) गरीब की झोपड़ी या कुटी। कुटिया के पर्यायवाची ही है बंगला, आश्रम, कुटी या झुग्गी-झोपड़ी। कुटिया आमतौर पर घास-फूस से निर्मित की जाती है। जब हम विनम्रता पूर्वक किसी को अपने घर आमंत्रित करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि हमारी कुटिया, हमारे गरीब खाने में भी पधारे। कुटिया से एक स्पष्ट तात्पर्य अपना घर भी होता है। लेकिन, इसका यह भी मतलब है कि प्रकृति से जुड़कर रहना।

कुटिया निर्माण की परंपरा आदिम युग से आरंभ हुई। मनुष्य अपने को सुरक्षित रखने के लिए जहां पर वह रहता था वहां कुटिया का निर्माण कर लेता था। जब मानव सभ्यता और आधुनिक तकनीकी का आविष्कार नहीं हुआ था। किंतु, धीरे-धीरे नवीन आविष्कारों के होने से कुटिया का चलन शहरों में बंद हो गया। लेकिन, आज भी लोग अपने फार्म हाउस पर कुटिया बनवा रहे हैं। क्योंकि। कुटिया में रहने का आनंद अलग प्रकार का होता है। कुछ होटल भी कुटियानुमा बनवा रहे हैं, जिसमें भारतीय शैली से भोजन भी बनाया जाता है और भारतीय शैली में ही बैठकर लोग भोजन का आनंद लेते हैं। छोटे -छोटे गांव, ढाणी में कुटिया आज भी विद्यमान है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले आज भी झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं।

भारत में ऋषि, मुनि, सन्यासी, तपस्वी अपनी साधना के लिए जंगलों में या पहाड़ों की चोटी पर कुटिया बनाकर साधना करते थे। हमारे धार्मिक ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। ऋषि, मुनियों का पूरा जीवन कुटियों में व्यतीत होता था। इन कुटियों में निवास करने वाले ऋषि -मुनियों के सात्विक जीवन की तरह और उसके आसपास का वातावरण ही बड़ा ही सात्विक और शांत होता था। ऋषि, मुनियों, सन्यासियों के शिष्य जब बढ़ जाते थे, तो कुटिया का विस्तार होकर पूरा क्षेत्र आश्रम में परिवर्तित हो जाता था। महाभारत में कण्व मुनि के आश्रम में दुष्यंत प्रवेश करते ही दुष्यंत का कथन है 'शान्तमिदमाश्रमपदं' यानी यह आश्रम कितना शांत है। कण्वमुनि के आश्रम में ही शकुंतला निवास करती है। शकुंतला को और तपोवन संस्कृति को देखकर दुष्यंत की युक्ति है -

शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य।
दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः।।

अर्थात् आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का इस प्रकार का रूप है जो अंतःपुर में भी दुर्लभ है तो निश्चय ही वन की लताओं ने अपने गुणों से उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। हमारे देश के आश्रम बहुत ही सुंदर होते थे। हमारा देश आश्रम संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज भी देश के किसी न किसी कोने में आश्रम विद्यमान है भले ही उनका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो गया है। उस समय वन की लताएं इतनी सुंदर थी जैसा कि आजकल नगर निगम के उद्यानों को सुंदर बनाया जा रहा है जिससे आमजन वहां के शुद्ध और शांत वातावरण में घूम सकें।

रामायण में जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तब वे वनवास काल में कई ऋषियों के आश्रम में पधारते हैं। शबरी जंगल में कुटिया बनाकर ही निवास करती थी और प्रभु राम के आगमन की प्रतीक्षा में आगमन के मार्ग और अपनी कुटिया को साफ सुथरा किया करती थी। राम उसकी कुटिया में आते हैं और उसके झूठे बेर प्रेम पूर्वक खाते हैं। वनवास काल में प्रभु श्रीराम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां वे अत्रि और माता अनुसूया द्वारा सत्कृत होते हैं। माता अनुसूया की आज्ञा से सीता वस्त्राभूषण धारण करती हैं और फिर वे वहां से आगे प्रस्थान करते है। इसके बाद श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और उनका अतिथि सत्कार ग्रहण करते हैं। पंचवटी के आश्रम में कुटिया (पर्णशाला) बनाकर राम, सीता, लक्ष्मण निवास करते हैं। पंचवटी की कुटिया से ही लक्ष्मण रेखा लांघने के कारण रावण द्वारा सीता का अपहरण होता है।

आदिम युग में लोगों का जीवन कुटिया में ही व्यतीत होता था। अतः कुटिया ही में सारे त्यौहार मनाए जाते थे। उस समय बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तो दीपक जलाकर कुटिया में रोशनी की जाती थीं। लक्ष्मी पूजन की परंपरा तो सतयुग से आरंभ हुई। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए लक्ष्मी पूजा तो त्रेता युग में भी किया जाता था। त्रेता युग में दीपावली के ही दिन प्रभु श्रीराम अयोध्या लौटे थे तो अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। पूर्वकाल में दिवाली पर कुटिया में निवास करने वाले साधु- संत, ऋषि -मुनि, तपस्वी- सन्यासी ,अमीर - गरीब, हर वर्ग के लोग अपनी कुटिया को गोबर व मिट्टी से लीपकर उसे नया स्वरूप देते थे। फिर सफेद खड़ियां, रंगीन रंगों व गेरुआ रंगों से रंग कर विभिन्न प्रकार की आकृति से उसे सुसज्जित करते थे। नेवैद्य और पुष्प चढ़कर लक्ष्मी गणेश का पूजन कर दिपावली का उत्सव मनाते थे।आज कुटिया में त्यौहारों का आशय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वे गांव में निवास करने वाले गरीब किसान वर्ग से हैं, जो मुश्किल से खेती से थोड़ा बहुत अन्न उत्पन्न कर अपना जीवन यापन करते हैं। समाज रहने वाले वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोग भी गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले के अंतर्गत आते हैं, जो त्यौहार मनाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं जिससे कि वे अपना खुशियां मना सकें।

पुस्तक चर्चा

डॉ. बिभा कुमारी

समीक्षक

हेतिः अधिकार और दायित्व के प्रश्नों के मध्य स्त्री

ख्यात लेखिक सिनीवाली का उपन्यास 'हेति' राजधर्म के बहाने स्त्री पर आघात की कथा वस्तु पर केंद्रित है। इस उपन्यास की कथा पितृसत्ता के अन्यायपूर्ण ढांचे पर कठिन सवाल खड़े करती है। राजकुमारी को महल में रखने मात्र से पिता का दायित्वपूर्ण हो जाता है? जब उसके जीवन पर संकट उपस्थित होता है तब पिता राजधर्म का हवाला देकर पुत्री को आंसुओं के समुद्र में डुबा देता है। भाई भी अपना उत्तराधिकार कायम रखने के लोभवश पिता के गलत निर्णय का विरोध नहीं करता है। पुरुषों के इस जड़ साम्राज्य में स्त्रियों की पुकार अरण्य रोदन ही सावित होता है।

सुकन्या राजकुमारी है और उसकी यह नियति है तो सामान्य स्त्री के साथ घटित अत्याचार की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। क्या भौतिक सुख -साधन उपलब्ध करवा देना मात्र ही पिता का कर्तव्य है? जब पुत्री के जीवन के लिए न्याय का चयन करना था तब पिता राजा बनकर राजधर्म का पालन करने को विवश हो गए। ये कैसा राजधर्म है जो अत्याचारी के हित में निर्णय लेता है? और यदि राजधर्म इतना अन्यायपूर्ण है तो राजा सिंहासन का परित्याग क्यों नहीं कर देते? क्या च्यवन ऋषि अकेले ही सुकन्या के साथ अन्याय करने के दोषी हैं? पिता, भाई और प्रेमी ने अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन किया? यदि सुकन्या का अपराध सचमुच अक्षम्य था तो च्यवन कैसे निर्णायक बन गए जबकि उन्होंने बारंबार आवाज देकर सुकन्या को दिग्भ्रमित किया था। उपन्यास तब से लेकर अबतक स्त्री के साथ हो रहे अमानवीय, अन्यायपूर्ण और असमानता के व्यवहार पर सोचने को विवश करता है।

पौराणिक कथाओं को समकालीन संदर्भों में देखने ङ्क समझने के लिए सिनीवाली के नवीनतम उपन्यास 'हेति' को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। उपन्यास स्त्री के व्यक्तित्व, उसकी अस्मिता और उसके परिचय के प्रश्न से जुड़े बिंदुओं को अत्यंत बेबाकी से उठाता है। स्त्री को छल ङ्क कपट इत्यादि के माध्यम से अपने अधीन किए जाने की विकृत मानसिकता के पुरुष को एक सशक्त स्त्री अपनी प्रतिभा और बौद्धिकता से पराजित कर देती है। च्यवन ऋषि के छल- कपट के आगे घुटने टेककर राजा ने अपनी सुपुत्री सुकन्या का विवाह तो ऋषि के साथ कर दिया पर क्या च्यवन ऋषि सुकन्या के हृदय में स्थान प्राप्त कर पाए? इसका जवाब है नहीं। पुरुष अपने अहंकार में डूबकर भले ही स्त्री को अपने अधीन कर लेने के भ्रम में फूला न समाए पर स्त्री की चेतना उसके इस कुकृत्य की घोर भर्त्सना करती है। वह उसके साथ रहकर भी उससे कोसों दूर रहती है। वह भोजन व पथ्य इत्यादि का इंतजाम मानवता मात्र के नाते से करती है। अपने व्यवहार से पुरुष को यह बतला भी देती है कि उसके मानव धर्म को प्रेम और समर्पण समझने की भूल न करे। कथावस्तु बेशक पौराणिक कथा पर केंद्रित है परंतु उसे समकालीन संदर्भों से जोड़कर बिल्कुल नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। नायिका प्रधान उपन्यास की श्रेणी में तो इसे रखा ही जाएगा। खास बात यह भी है कि सभी स्त्री पात्र अत्यंत सशक्त रूप में उभरकर आई हैं। प्रमुख व गौण सभी स्त्री पात्र इतनी मजबूती से प्रस्तुत हुई हैं कि उनके समकक्ष कोई भी पुरुष पात्र नहीं पहुंच पाया है यहां तक कि सुकन्या का प्रेमी भी सुकन्या, उसकी सखि या महारानी के पासंग नहीं पहुंच पाया है।उपन्यास में राजमहल से लेकर वन तक के परिवेश को अत्यंत जीवंत रूप में चित्रित किया गया है।

उपन्यास की भाषा अत्यंत आकर्षक है,

कथावस्तु, पात्र और परिवेश के अनुकूल है। आज जब भाषा संकट के दौर से गुजर रहा है यह उपन्यास इस दृष्टि से आश्वस्तिदायक है कि अभी युवा हिंदी उपन्यासकारों की शब्दावली पर्याप्त समृद्ध है और उनमें युग और परिवेश के अनुकूल भाषाई प्रयोग की कुशलता विद्यमान है। उपन्यास की पठनीयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाठक अपने वर्तमान को विस्मृत कर वर्णित युग में स्वयं को महसूस करने लगता है।

आधुनिक साहित्य में विद्वानों ने उपन्यास को महाकाव्य की कोटि की रचना कहा है और यह कथन उपयुक्त भी है। वृहद केन्द्रीय कथा को अन्य उपकथाओं के साथ समायोजित कर लिखी जानेवाली यह विधा पाठकों के बीच अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रखती है। यही कारण है कि उपन्यासकारों से पाठक की उम्मीदें भी बहुत अधिक होती हैं। प्रायः पाठक ऐसी उम्मीदें वरिष्ठ उपन्यासकारों से करते हैं तथा युवा उपन्यासकारों को थोड़ा कम गंभीरता से लेते हुए यह मानकर चलते हैं कि अभी इन्हें बहुत कुछ सीखना है। ऐसे में अचानक युवा उपन्यासकार सिनीवाली ने 'हेति' उपन्यास लिखकर पाठकों और आलोचकों को चौंका दिया है। प्रथमतः इस उपन्यास का स्वागत होना चाहिए। जिस तरह के उपन्यास की अपेक्षा आज के युवा रचनाकारों से करना लोग भूलने लगे थे उस तरह का उपन्यास लिखकर उन्होंने एक आश्वस्ति दी है कि युवा रचनाकारों से आप बड़ी अपेक्षाएं करिए। वे आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का माद्दा रखते हैं। वास्तव में 'हेति' सुकन्या के माध्यम से संसार की समस्त नारियों के हृदय में बसी पीड़ा की अग्नि और इच्छा -अनिच्छा से ऊपर उठकर निभाए जा रहे कर्तव्यों की अग्नि का प्रतीक है। इसी कर्तव्य की अग्नि में स्वयं को होम करती हुई स्त्री अपने अस्तित्व को धुँधला होते हुए और फिर धीरे - धीरे मिटते हुए देखती है। पर उसे इस बारे में कुछ बोलने का न अवसर दिया जाता है और न ही समय। उसकी सेवा - टहल के बदले उसे धर्मपरायण स्त्री की उपमा देकर प्रशंसा के पुल बाँधे जाते हैं, परंतु उसके जीवन से छीज रहे जीवन को बचाने का प्रयास किसी की ओर से नहीं होता है।

उपन्यास की विषय - वस्तु राजकुमारी सुकन्या और च्यवन ऋषि के विवाह की पौराणिक कथा पर केंद्रित है। 'उपन्यास' के केंद्र में स्त्री की अस्मिता का प्रश्न है और यह शुरू से अंत तक केंद्र में बना रहा है। कहीं भी उपन्यासकार विषय - वस्तु को लेकर दिग्भ्रमित नहीं हुई है। उपन्यास में सुकन्या के अतिरिक्त भी कई स्त्री पात्र हैं सबके जीवन में दुख, उपेक्षा, संघर्ष है। जीवन के कठिन रास्तों पर चलते हुए अपने जीवन की आहुति देनी है। किसी भी युग और किसी भी देश में यदि स्त्री के अस्मिता को ठेस पहुँचती है तो उस पूरे परिवेश में जीने वाले मनुष्य मात्र के विवेक पर प्रश्न उठता है। राजकुमारी का एक वृद्ध ऋषि से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया जाना और रानी का पुत्री के वियोग में प्राणांत हो जाना अंग्रेजी के त्रासदी नाटकों से भी अधिक पीड़ादायी और मन - मस्तिष्क को झकझोर कर रख देनेवाला है।

जिस पौराणिक कथा को वर्षों से इतने सामान्य ढंग से कहते - सुनते चले आ रहे हैं उसके भीतर कितनी परतें हैं। इन परतों को हटाकर जब देखने - परखने का एक प्रयास उपन्यासकार करती हैं तो मानवता कहीं अपने लिए स्थान नहीं ढूँढ पाती है। उसे प्रश्नों के कठघरे में खड़ा होना पड़ता है। स्त्री - पुरुष असमानता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक वृद्ध ऋषि के अनुचित माँग को भी राजा और प्रजा सभी स्वीकार कर लेते हैं और फूल जैसी राजकुमारी के साथ हो रहे अन्याय का विरोध नहीं करते हैं। विपत्ति की इस घड़ी में थोड़ा सा सहारा देने का साहस भी उसकी सखी उर्वी अर्थात एक नवयुवती ही करती है। राजकुमारी के काँपते शरीर को थामकर खड़ी हो जाती है।

अन्य सभी इसे स्त्री जीवन की नियति मानकर अपनी मूक सहमति दे देते हैं। उपन्यास के केंद्र में यही प्रश्न है कि एक राजा द्वारा राजधर्म के नाम पर अपनी ही पुत्री का बलिदान क्या उचित है? और यदि राजधर्म को निभाते हुए ऐसा करने की विवशता है तो राजा के पद का त्याग करके सिर्फ पिता नहीं बना जा सकता है? कथा यद्यपि पौराणिक है परंतु प्रश्न तो वर्तमान में भी उपस्थित है। हो सकता है कि सुकन्या की पौराणिक कथा में तथ्यों की पूर्णता का अभाव हो, परंतु कुछ न कुछ तो कथा में तथ्य भी है जिसकी पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास रचा जा रहा है और संपूर्ण मानव जाति पर प्रश्न उठाया जा रहा है।

उपन्यास - हेति
लेखिका- सिनीवाली
प्रकाशन- रुद्रादित्य प्रकाशन, प्रयागराज
मूल्य- 300/-

नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार निर्धारित नहीं, नियमों की अनदेखी भी हादसों के लिए जिम्मेदार

कहीं डिवाइडर तोड़कर बना लिया रास्ता, तो कहीं सूख रही मक्का, नतीजा, बढ़ रहें सडक़ हादसे

संजय द्विवेदी, बैतूल। नेशनल हाइवे निर्माण से बेहतर सडक़ों की सुविधा तो मिली है, लेकिन हाइवे पर वाहनों की रफ्तार पर कंट्रोल नहीं है। यहीं वजह है कि हाइवे पर आए दिन दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे वाहनों की तेजी रफ्तार के अलावा लोगों की लापरवाही भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। हाइवे पर बने डिवाइडर लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार तोडक़र रास्ता बना लिया है, तो कहीं-कहीं हाइवे के किनारे बसे गांवों के किसान सडक़ पर उपज डालकर सूखाने का काम कर रहे है। जिससे वाहन चालक गाड़ी चलाते समय भ्रमित होकर हादसा का शिकार हो रहे है। यह स्थिति नागपुर की ओर मुलताई तक और भोपाल की ओर शाहपुर तक अधिकांश जगहों पर देखी जा रही है। जिससे यह कहा जा सकता है कि मार्ग इन दिनों मक्का आदि उपज सुखाने और अतिक्रमण करने वालों के कब्जे में है। लोगों के द्वारा जगह-जगह पर मुख्य सड़क पर ही मक्का सुखाया जा रहा है। कई बार कई वाहन चालक फिसल कर गंभीर रूप से चोटिल भी हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसी मार्ग से दर्जनों बार प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाही नहीं करते है। जिससे हाइवे की सडक़ों पर उपज सूखाने वालों का कब्जा बढ़ता जा रहा है।

डिवाइडर तोडक़र मनमर्जी से बना लिया रास्ता- नेशनल हाइवे फोरलेन मार्ग के बीच डिवाइडर बनाकर उसमें पौधे लगाए गए है। मुलताई से इटारसी के बीच विभिन्न स्थानों पर लोगों ने डिवाइडर को तोडक़र रास्ता बना लिया है। जिससे एक लेन से दूसरे लेन पर पहुंचते हैं। डिवाइडर तोडक़र बनाए गए रास्ते से दो पहिया और चार पहिया वाहन भी निकलते हैं। इस दौरान थोडी सी लापरवाही हादसे का कारण बनते जा रही है। इसके बाद भी एनएचएआई के अधिकारी ध्यान नहीं दे रही है। हाइवे पर गांवों के जोड, पेट्रोल पंप और ढाबों के पास डिवाइडर टूटे हुए है। डिवाइडर के बीच से दूसरे लेन पर आने के दौरान हाईवे से तेज गति से गुजरने वाले वाहनों से टक्कर हो रही है। सबसे अधिक घटनाएं रात के समय हो रही है। डिवाइडर के बीच से बाइक सहित अन्य वाहन निकालने के दौरान हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की गति का अंदाजा नहीं लग पाता है। डिवाइडर से हाईवे पर वाहन पहुंचते ही टक्कर हो जाती है।

कई वाहन चालकों को नहीं पता नियम - हाईवे पर वाहन चालक चलाने के लिए अलग-अलग लेन होती है। इसमें हैवी वाहनों के अलावा छोटे चार पहिया वाहन और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से लेन है, लेकिन कई वाहन चालकों को इसकी जानकारी नहीं होती है। अक्सर देखा जाता है कि दोपहिया वाहन चालक हाइवे पर पहली या दूसरी लेन पर वाहन चलाते है। जिससे तेज गति से आने वाले वाहनों के कारण हादसों का शिकार होते है। इसके अलावा चालक वाहनों की गति भी निर्धारित सीमा में नहीं रखते है। कई बार वाहनों की तेज गति के कारण वाहन अनियंत्रित हो जाते है और डिवाइडर या अन्य वाहनों से टकराकर हादसों का शिकार होते है।

भोपाल जाते समय हाईवे पर पलटी बस, 20 से अधिक यात्री घायल

बैतूल/शाहपुर। भोपाल हाईवे पर यात्रियों से भरी निजी कंपनी की बस पलट गई। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गये। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने घायलों को शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया है, वहीं गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब ढाई बजे भोपाल ट्रेवल्स की बस हाईवे पर भौरा के पास धपाड़ा जोड़ पर बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के समय बस में 32 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि मोड पर ड्राइवर बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और वह झोंका खाकर पलट गई। यात्रियों ने बताया कि जिस समय हादसा हुआ। बस में सवार सभी यात्री गहरी नींद में सोए हुए थे। जोर की आवाज के साथ जब बस पलटी तो उन्हें झाड़ी का अहसास हुआ। यात्रियों का कहना है कि बस काफी तेज रफ्तार में थी, जैसे ही बस पलटी, तेज आवाज आई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गये। जबकि 8 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रविवार बस को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाने की कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस घटना की जांच की जा रही है।

अनियंत्रित हुई बाइक, एक की मौत, एक घायल

बैतूल-आमला रोड पर उमरी गांव के पास बाइक तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सडक़ से उतरकर गन्नाबाडी में घुस गई। घटना में बाइक पर सवार एक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा एक अन्य घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। आमागोहान निवासी ललित पिता भूरा नवडे (32) अपने जीजा त्रिलोक सलाम के साथ बघवाड़ से बाइक पर बैठकर अपने गांव आमगोहान लौट रहे थे। बाइक ललित चला रहा था, जबकि त्रिलोक पीछे बैठा हुआ था। उमरी के पास तेज गति से बाइक अनियंत्रित होकर सडक़ से उतरकर गन्नाबाडी में घुस गई। इस घटना में बाइक चला रहे ललित की मौत हो गई, जबकि त्रिलोक घायल हो गया। गंज टीआई रविकांत डेहरिया ने बताया मृतक का शव जिला अस्पताल लाए हैं। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है।

नगर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई आंवला नवमी

विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने की पूजा-अर्चना

बैतूल/भौंरा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर नगर में रविवार को आंवला नवमी का पर्व पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर के प्रमुख स्थलों पर आंवले के वृक्ष की पूजा की गई, जिसमें खेड़ापति माता मंदिर परिसर के पास स्थित आंवला वृक्ष प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। सूर्योदय के साथ ही नगर की महिलाओं ने विभिन्न स्थानों पर आंवले के पवित्र वृक्ष की पूजा कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

इस धार्मिक आयोजन में नगर के अलग-अलग हिस्सों से महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सजकर पूजा स्थलों पर पहुंचीं। खेड़ापति माता मंदिर के पास महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा की, जिसके बाद वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने बच्चों के साथ उसके नीचे भोजन ग्रहण किया। इस दौरान अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार आंवला वृक्षों की पूजा कर महिलाओं ने अपनी आस्था प्रकट की और पूजा के बाद पेड़ के नीचे भोजन किया। पर्व में शामिल श्रद्धालुओं ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक मानकर विधिपूर्वक पूजन किया। स्थानीय निवासी दीपिका राठौर, रोशनी,ज्योति, प्रीति, सोना तिवारी, संगीता साहू, ज्योति राठौर ने बताया कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सुख-समृद्धि प्राप्त होती है और संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। वहीं, पूजा में उपस्थित श्रद्धालु ने कहा कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना संतान की सेहत और भविष्य के लिए शुभ माना गया है। नगर के विभिन्न पूजा स्थलों पर महिलाओं के साथ बच्चों ने भी इस पर्व में उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्थानीय निवासी और श्रद्धालु सविता यादव ने कहा कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और हर वर्ष महिलाएं आंवला नवमी पर इस पूजन में शामिल होकर अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। इस आयोजन के माध्यम से आस्था, परंपरा और परिवार के प्रति प्रेम का संदेश मिलता है। आंवला नवमी पर नगर की महिलाओं ने परिवार संग पूजन और प्रसाद ग्रहण कर परंपराओं का निर्वहन किया, जिससे नगर में धार्मिक माहौल बना रहा।

आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना

बैतूल/शाहपुर। रविवार को आंवला नवमी धूमधाम से मनाई गई। मंदिर में महिलाओं के द्वारा आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने बताया कि इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बडा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इससे वर्ष आयु-आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। महिलाओं द्वारा लमटी बजरंग मंदिर पहुंचकर वहां पर स्थित आंवले के वृक्ष की पूजा की एवं पंडित सिंटू परसाई के द्वारा विधि विधान से आंवला नवमी का पूजन अर्चन करवाया गया। महिलाओं ने विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत पूजन किया गया।

अज्ञात कारणों से सोयाबीन की खराई में लगी आग

बैतूल। अज्ञात कारणों से सोयाबीन की खराई में आग लग गई। इस हादसे में 6 एकड़ में लगी सोयाबीन की फसल बुरी तरह जल गई। सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम खतेडाकला में रविवार को दो किसानों के खेत में रखी सोयाबीन की खराई में आग लग गई। किसानों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल को दी। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। दमकल कर्मचारी ने बताया कि खराई में लगभग 6 एकड़ की फसल दावन के लिए रखी गई थी। अज्ञात कारणों से लगी आग के कारण सोयाबीन की फसल धू-धू कर जलने लगी। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आगजनी की इस घटना में लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान होना बताया जा रहा है।

संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, पुलिस कर रही जांच

बैतूल। चोपना थाना क्षेत्र स्थित मनकाढाना में रविवार को एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिला है। पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए घोड़ाडोंगरी अस्पताल भेजा। प्रारंभिक तौर पर करंट से मौत होना बताया जा रहा है। लेकिन, पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनों बिन्दुओं पर जांच कर रही है। एसडीओपी रोशन जैन ने बताया कि मनका ढाना में सन्नू पिता चुन्नीलाल अखंडे (40) का शव उसी के खेत के पास जंगल में मिला है। शव को प्रथम दृष्ट्या देखने पर मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। शव का रविवार सीएचसी घोड़ाडोंगरी में पीएम करवाया गया है। जिसकी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। प्राथमिक तौर पर यह करंट लगने से मौत का मामला लग रहा है। लेकिन, इस पर अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक एक दिन पहले अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, इसके बाद वापस नहीं लौटा। इसके बाद तलाश करने पर उसका शव खेत के पास ही जंगल में मिला। हालांकि, शव के सिर और अन्य अंगों से खून निकलने से यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। यही वजह है, कि पुलिस इसे हत्या से भी जोडक़र देख रही है। पुलिस ने खेत से करंट लगाने वाला सेंटरिंग वायर भी बरामद किया है, जो अक्सर फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए आसपास लगा दिया जाता है। एसडीओपी ने बताया कि इस मामले में निष्कर्ष पर अगले एक दो दिन में ही पहुंचा जा सकता है। फिलहाल विवेचना एकदम प्रारंभिक स्तर पर है।

हौंसले अगर बुलंद हो तो कोई भी बड़ी कामयाबी पाना बहुत आसान होता: बनकर

यूपीएससी में सफल हुए हिमांशु सिंह ठाकुर का हुआ सम्मान

बैतूल। रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) थाना प्रभारी राजेश बनकर ने कहा कि हिमांशु सिंह ठाकुर को यूपीएससी से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर (कॉरपोरेट लॉ) जैसे महत्वपूर्ण पद पाने में मिली सफलता यह बताती है कि यदि हौसले बुलंद हो तो कोई भी बडी कामयाबी पाना बहुत आसान सा हो जाता है। श्री बनकर स्टेशन परिसर में हिमांशु सिंह के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेशन प्रबंधक वी.के. वाकडे ने की। इसके पूर्व हिमांशु का करतल ध्वनि के बीच थाना प्रभारी राजेश बनकर आदि ने शाल, श्रीफल से सम्मान किया। विदित हो कि वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह ठाकुर एवं उषा सिंह के पुत्र हिमांशु सिंह ने बीते माह यूपीएससी द्वारा असिस्टेंट डायरेक्टर (कॉरपोरेट लॉ) के 12 पदों के लिए घोषित हुए परीक्षा परिणाम में ऑल इंडिया 10वीं रैंक प्राप्त की थी। आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने अपने संबोधन में कहा कि हिमांशु को मिली सफलता प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों में प्रेरणा का काम कर उन्हें आगे बढ़ने का सकारात्मक संदेश देगी। उन्होंने हिमांशु से उम्मीद जताई कि वे जिले के बच्चों को अपना बेहतर करियर बनाने में समय-समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। कॉरपोरेट लॉ में अस्सिटेंट डायरेक्टर के लिए चयनित हिमांशु सिंह ठाकुर ने सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने पर आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर को धन्यवाद देते हुए कि कहा कि जिले में अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो पढाई के साथ-साथ विद्यार्थियों का करियर बनाने पर भी काम कर रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए तैयारी में जुटने का आह्वान किया. मेहनत से लक्ष्यों को पाना आसान है. मैने सफलता प्राप्त की है तो अन्य लोगों के लिए भी सफलता प्राप्त करना संभव है। सम्मान समारोह में रेलवे के एसएसई टेलीकॉम अनुराग दुबे, वाणिज्य निरीक्षक पंकज कुमार,एसएसई सिग्नल पी.आर.डांगे, डायटिशियन एवं समाजसेवी मनोज वाधवा ने अपने संबोधन में हिमांशु को मिली कामयाबी पर बधाई देते हुए बच्चों से अपना भविष्य बनाने के लिए लक्ष्य तय कर सफलता प्राप्त करने का आव्हान किया। कार्यक्रम में आरपीएफ के संतोष पटेल,पंकज जैन, दिलीप चौकीकर,देवेंद्र सिंह ठाकुर, श्री रावत आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज वाधवा ने किया।

प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

महिला एवं पुरुष वर्ग की दर्जनों टीमों ने लिया भाग

बैतूल/ मुलताई। मुलताई नगर के उत्कृष्ट विद्यालय बास्केटबॉल ग्राउंड पर प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें संपूर्ण प्रदेश से महिला एवं पुरुष वर्ग की एक दर्जन से भी अधिक टीमों ने भाग लिया। मुलताई नगर में यह पहली बार है कि महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का प्रदेश स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। समाचार लिखे जाने शाम 6 बजे तक पुरुष एवं महिला वर्ग में सेमीफाइनल स्तर के मैच हो चुके थे। फाइनल मैच देर रात तक होगा। महिला वर्ग में सेमीफाइनल में बैतूल टीम पहुंची है और दूसरे सेमीफाइनल के लिए महिला वर्ग के मुलताई एवं नर्मदा पुरम के बीच गेम खेला जा रहा था। इस प्रतियोगिता में विजय टीम बैतूल बास्केटबॉल महिला टीम से फाइनल में खेलेगी ।अब तक महिला एवं पुरुष वर्ग में कुल 9 मेंच हुए हैं और टोटल दोनों वर्ग को मिलाकर 17 मैच खेले जाने हैं। आयोजन मंडल में शामिल विशाल भारती ने बताया कि पुरुष वर्ग में छिंदवाड़ा इटारसी नर्मदा पुरम मुलताई एवं बैतूल की टीम एवं महिला वर्ग में भोपाल, छिंदवाड़ा, बैतूल, मुलताई, नर्मदा पुरम की बास्केटबॉल टीम भाग ले रही है। प्रथम विजेता टीम को ?5000 एवं फील्ड का वितरण विधायक चंद्रशेखर देशमुख द्वारा किया जाएगा वही उपविजेता को ?3100 नगद इनाम के साथ फील्ड प्रदान की जाएगी ,प्रथम उपविजेता टीम को ?2100 और द्वितीय उपविजेता टीम को ?1100 नगद एवं शील्ड ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु आयोजित इस प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में सचिन पाल ,आकाश माहौरे, मितेश गुलतकर, विशाल सोनी ,गोलू ओमकार आदि की सारणी भूमिका रही।

अतिथि शिक्षक ने खाया जहर, उपचार के दौरान मौत

बैतूल। अतिथि शिक्षक ने जहर खा लिया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल पुलिस चौकी के मुताबिक शनिवार रात आठनेर थाना क्षेत्र के गुजर माल निवासी सागर चढोकार (36) को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था। सागर शनिवार घर पर अकेला था। उनकी मां गांव में कहीं गई हुई थी। भाई प्राइवेट जॉब से चिचोली गए हुए थे। मां जब गांव से वापस घर लौटी तो सागर बेसुध पड़ा हुआ था। उसके पास से जहर की स्मैल आ रही थी। मां ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सागर भीमपुर विकासखंड के चिल्हौर के पास हाईस्कूल में अतिथि शिक्षक था। वह लंबे समय से डिप्रेशन में था। जिसका नागपुर में इलाज किया जा रहा था। वह दिवाली के छुट्टी पर चिल्हौर से गुजरमल आया हुआ था।

खस्ताहाल घोषित होने के वर्षों बाद भी नहीं निकला 17 दुकानों का हाल

अधिकारियों ने जर्जर दुकानों पर जताई थी चिंता, जांच में बास लगने से टूट रही थी छत

बैतूल/ मुलताई। मुलताई नगर पालिका की ताप्ती तट पर स्थित 17 दुकान जर्जर कंडम और चिंताजनक घोषित हुए 3 वर्षों से अधिक गुजर गए है किंतु इसके बावजूद भी इन दुकानों का कोई हल नहीं निकल सका है लोगों का मानना है कि प्रशासन जब चेतेगा जब कोई गंभीर हादसा होगा लेकिन ऐसा होने पर वह राजनीतिक भी दोषी होंगे जो इस दुकान को हटाए जाने में बाधा बनते हैं। जब भी इन 17 दुकानों को हटाए जाने के प्रयास प्रारंभ होते हैं राजनीतिक अंड़ागो के चलते यह मामला टल जाता है किंतु जिस प्रकार यह दुकाने ताप्ती सौंदरीकरण की बड़ी समस्या है और जिस रफ्तार से इसका निर्माण क्षतिग्रस्त हो रहा है भविष्य में गंभीर हादसा हो सकता है। हाल ही में जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने दुकानों को हटाए जाने की सार्थक पहल प्रारंभ की थी और यह माना जा रहा था कि जिला कलेक्टर के प्रयासों से अब इस समस्या का स्थाई हल हो सकेगा किंतु हमेशा की तरह इस बार भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते मामला टल गया।

जांच अधिकारियों ने बताया था दुकानों को जर्जर और चिंताजनक- प्रदेश में जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है जर्जर हो गई 17 दुकानों की जांच अवश्य होती है बीते 10 सालों में दर्जनों बार दुकानों की जांच हो चुकी है और हर बार इस निर्माण पर चिंता व्यक्त की गई। 17 जुलाई 2021 को नगर पालिका एवं लोक निर्माण की संयुक्त टीम ने इन 17 दुकानों की जांच की थी। जब अधिकारियों की उपस्थिति में नगर पालिका कर्मचारी इन दुकानों की जांच कर रहे थे तब बास लगाने से छत टूट रही थी। इस जाच दल में शामिल तत्कालीन लोक निर्माण एसडीओ एके जैन ने बताया था कि 17 दुकानों की जांच में यह पाया गया है की निर्माण की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है बास लगने से छत टूट रहा है दुकानों के निर्माण में लगा 10 एमएम का लोहा 2 एमएम रह गया है।

ताप्ती सौंदर्य के लिए दुकानों का हटना आवश्यक

ताप्ती सरोवर सरोवर मात्रा न होकर नगर वासियों की आस्था का प्रतीक भी है और नगर की पहचान भी क्योंकि इसे ताप्ती कुंड माना जाता है। जहां से ताप्ती तीन प्रदेशों को सुख और समृद्धि का वरदान देने निकलती है ।यही कारण है कि ताप्ती सौंदर्य करण की मांग लंबे समय से होती रही है किंतु ताप्ती के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों ने कभी इस पवित्र धाम को व्यवस्थित विकास से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। जब भी ताप्ती सौंदर्य की बात आती है 17 दुकान सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है हालांकि जिन लोगों को निर्माण के वक्त यह दुकान आवंटित हुई थी अब इनमें से अधिकांश व्यापारी बदल गए हैं अनेक दुकानें दूसरी ओर शिफ्ट हो गई है अनेक दुकानें किराए से चल रही है दुकानदार भी ताप्ती से आस्था के कारण इसका विरोध नहीं करते हैं किंतु उनका कहना है कि उन्हें दूसरे स्थान पर बसाया जाए व्यापारियों और नगर प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है।

भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

जयंती

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता

स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा 11 सितंबर 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। तभी से भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मौलाना आज़ाद के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों,प्रयासों, कार्यों और योगदान के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को शिक्षा के अधिकार और शिक्षा के महत्व व आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2022 की थीम पाठ्यक्रम को बदलना,शिक्षा को बदलना थी। वर्ष 2023 की थीम मतलब शिक्षा में नवाचार को अपनाना थी। इस थीम के द्वारा पढ़ने पढ़ाने के लिए सृजनात्मक अध्यापन के आधुनिक तरीकों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया गया था। राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका कितनी अहम है यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री बखूबी जानते थे। इसलिए शिक्षा को सरल,सहज,अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंच और शिक्षा प्रणाली को आधुनिक व कारगर बनाने के लिए कई अभिनव प्रयोग उनके द्वारा किए गए। मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में ही देश का पहला आईआईटी 1951 में स्थापित किया गया इसके बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना की गई। इसी क्रम में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन,आईआईएससी,अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और संपूर्ण देश में ख्याति प्राप्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके अतिरिक्त मौलाना आज़ाद ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, साहित्य अकादमी,संगीत नाट्य अकादमी और ललित कला अकादमी का गठन भी किया। मौलाना आज़ाद का मानना था कि ये संस्थान भविष्य में भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम के पिता का नाम खैरुद्दीन देहलवी था जो 1857 में भारत छोड़कर मक्का में बस गए थे वहीं उन्होंने एक अरब महिला से विवाह किया। मौलाना आज़ाद के पिता सूफी थे। उन्होंने आज़ाद को घर पर ही धर्मशास्त्र के साथ- ही- साथ अरबी,फ़ारसी और उर्दू की भी शिक्षा दी। मौलाना आज़ाद ने अपना अधिकांश लेखन उर्दू में ही किया। मौलाना आज़ाद ने उर्दू में कुरान पर एक टीका 1921-1923 के बीच लिखी जब उन्हें दुबारा गिरफ्तार किया गया था। यह बाद में तरजुमला अल-कुरान शीर्षक से 1931 में प्रकाशित हुई। यह टीका अपूर्ण है, लेकिन अपने पहले खंड के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। यह पहला खंड पूरी तरह से कुरान के पहले अध्याय अल-फ़ातिहा पर केंद्रित है। मौलाना आज़ाद द्वारा कुरान पर लिखी गई टीका को अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जाता

है। पारंपरिक इसलामिक ग्रंथो के अध्येता होने के साथ वे ज्ञान के दूसरे रूपों के अध्ययन में भी गहरी रुचि रखते थे। वे ऐसे पश्चिमी ज्ञान और मूल्यों का स्वागत करते थे जो इसलाम की नैतिक शिक्षाओं के अनुरूप लगते थे। वे बौद्धिक रूप से खुद को मध्ययुगीन भारतीय विद्वान शेख अहमद सरहिंदी का अनुयायी मानते थे। मौलाना आजाद ने अपने लेखन में सैयद अहमद खां की भी काफी तारीफ़ की है लेकिन वे उनके द्वारा अपनायी गई अंग्रेजी- निष्ठा के आलोचक भी थे। 1912 में मौलाना आज़ाद ने एक साप्ताहिक पत्रिका अल-हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद 1915 में उन्होंने अल-बग़ल पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू की। इन पत्रिकाओं व अपनी अन्य गतिविधियों के माध्यम से वे मुसलमानों में एक ऐसी धार्मिक भावना जगाना चाहते थे जिससे वे खुद को भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ सकें। मौलाना चाहते थे कि मुसलमान अधिक से अधिक संख्या में देश के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हों। 1916 में अंग्रेजों ने उनकी प्रेस को बंद करवा दिया और उन्हें कैद कर कारावास में डाल दिया। अपनी राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता के कारण मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आये। आज़ाद ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन और ख़िलाफ़त आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ काम किया। आज़ाद मुसलमानों और गांधी के बीच जुड़ाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए, क्योंकि वे मुसलमानों के बीच अहिंसक राजनीतिक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमान समुदाय की एकता और भागीदारी के लिए एक इसलामिक कार्यक्रम पेश करने की कोशिश की जिस पर जमाल अल-दीन अफगानी और शिबली नोमानी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव था। इन दोनों से काफ़ी प्रभावित मौलाना आज़ाद ने इसलाम के संदर्भ में भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया। मौलाना आज़ाद 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। इसके बाद 1940 व 1946 में भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। अपने कई समकालीनों के विपरीत मौलाना आज़ाद ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी स्थिति और हित पर हिंदुओं और मुसलमानों के रूप में विचार न करके उन्हें किसान या जमींदार,मजदूर या पूंजीपति के रूप में विचार करना चाहिए। वे मानते थे कि वास्तविक आज़ादी तब तक नहीं आ सकती हैं जब तक हर व्यक्ति को अवसर की समानता और आर्थिक आज़ादी न मिले।

मौलाना आजाद इसलामिक धर्मशास्त्र और आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली बौद्धिकों में से एक थे जो सेकुलर राष्ट्र और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के पैरोकारी थे। मौलाना आजाद को मुख्य रूप से उनकी विद्वता और मौलिकता के लिए याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा महिला शिक्षा के लिए की गई पुरजोर वकालत और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा की सशक्त अवधारणा के लिए खास तौर पर याद किया जाता है।मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथात्मक किताब इंडिया विंस फ़रीडम जिसकी पूरी पांडुलिपि उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार को इस हिदायत के साथ सौंप दी थी कि उनकी मृत्यु के तीस वर्ष बाद उसे प्रकाशित किया जाए। इस किताब को 1988 में प्रकाशित किया गया। इसके पूर्व 1916 में जब वे जेल में थे तब उन्होंने अपनी आत्मकथा तज़किरा भी लिखी थी। मौलाना आजाद को मरणोपरांत 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है।

(शेष अगले कॉलम में)

कटनी में गर्भवती युवती ने ट्रेन से कटकर दी जान

पिता बोले- युवक की शिकायत करने थाने गई थी, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

कटनी (नप्र)। कटनी में माधवनगर थाना क्षेत्र के कटनी-जबलपुर रेल खंड में एक गर्भवती युवती ने शुक्रवार रात ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में शनिवार को परिजनों और क्षेत्र के लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजनों और क्षेत्र के लोगों ने माधवनगर गेट के पास रास्ते जाम लगाने का प्रयास करते हुए विरोध जताया। जिसकी सूचना पर मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया।

ये है पूरा मामला- थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर ने बताया कि अमीरगंज क्षेत्र निवासी युवती ने शुक्रवार रात ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने माधवनगर गेट पर रास्ता रोककर जाम लगाने का प्रयास किया। समझाइश के बाद विरोध शांत हो गया है। पुलिस पर जो कार्रवाई ना करने के आरोप लगे हैं। उनकी जांच भी की जा रही है।

जंगल में गला घोंटा, फंदे पर लटकाकर सुसाइड दिखाया

प्रेमिका ने पिता-बेटे के साथ मिलकर किया ठेकेदार का मर्डर ; बोली- ब्लैकमेल करता था

अनूपपुर (नप्र)। अनूपपुर पुलिस ने 31 अक्टूबर को जंगल में दिलीप यादव नाम के व्यक्ति का शव मिलने के मामले में खुलासा किया है। दिलीप की हत्या उसी की प्रेमिका ने अपने पिता और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर की थी। सुसाइड दिखाने के लिए शव को फंदे पर टांग दिया। युवक महिला को ब्लैकमेल कर रहा था।

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शनिवार को युवक की प्रेमिका कलावती पाव (35), उसके पिता बारेलाल पाव (63) और 16 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया ने कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद जैन से बात कर मामले को समझा।

जंगल में महुआ के पेड़ पर लटका मिला था शव- 31 अक्टूबर यानी दिवाली की सुबह संदीप यादव निवासी ग्राम बिजौड़ी ने कोतवाली पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। बताया कि उसका मामा दिलीप यादव (35) पिता प्रीतम यादव निवासी वनगवां 30 अक्टूबर की शाम से लापता है। उसने बताया कि दिलीप पेशे से ठेकेदार है। बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की।

पुलिस ने दिलीप की मोबाइल लोकेशन चेक की। लोकेशन ग्राम भोलगढ़ के जंगल में मिली। सर्चिंग में दिलीप का शव जंगल में महुआ के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। गले में नाखून और गर्दन में पीछे चोट के निशान मिले। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवक की मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की।

कॉल डिटेल से अवैध प्रेम संबंध का खुलासा- पुलिस ने दिलीप और संदेहियों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। पता चला कि जिस नंबर से आखिरी बार दिलीप की बात हुई थी, वह कलावती पाव का है। उसका पति बैजनाथ पाव निवासी भोलगढ़ दिलीप यादव के यहां दो साल पहले मजदूरी करता था। इसी के चलते उसका बैजनाथ के घर आना-जाना था।

इसी दौरान कलावती और दिलीप के बीच दोस्ती हो गई। पिछले दो साल पहले बैजनाथ काम करने मुंबई चला गया। कॉल डिटेल में पता चला कि लगातार दो साल से इस नंबर पर देर रात तक बातचीत होती थी। दोनों भोलगढ़ के पास जंगल में मिलते थे। इसके बाद बारेलाल और कलावती से पूछताछ की गई। दोनों पहले तो बरगलाने लगे। सख्ती करने पर आरोपी ने वारदात कबूल कर ली।

दिलीप को मिलने बुलाया और गला घोंट दिया- पुलिस के मुताबिक 30 अक्टूबर की शाम कलावती ने कॉल करके दिलीप को घर के पीछे भोलगढ़ के जंगल में बुलाया। यहां दिलीप को बातों में लगा लिया। इसी दौरान पिता बारेलाल और बेटे ने पीछे से आकर दिलीप को पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर दिलीप का गला घोंट दिया। उसकी मौत हो गई।

हत्या को सुसाइड बताने के लिए पास में लगे महुआ के पेड़ पर गमछे का फंदा बनाकर टांग दिया, जिससे लगे कि ठेकेदार ने फांसी लगाई है। जांच में पता चला कि जिस गमछे से दिलीप का शव लटका था, वह उसका नहीं था, बल्कि कलावती के पिता बारेलाल का है।

बदनाम करने का डर दिखाकर ब्लैकमेलिंग- कलावती ने बताया कि दोनों के संबंधों के बारे में पति बैजनाथ को पता भी नहीं था। पूछताछ में पता चला कि पिछले कुछ दिनों से ठेकेदार महिला को बदनाम करने का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। एक बार महिला से 20 हजार रुपए ऐंठ लिए।

प्रकृति वात्सल्य गौशाला धार में गौ पूजन, गौसेवकों , पशु चिकित्सकों, समाजसेवियों का हुआ सम्मान ...

गोचर भूमि बचाओ, गाय बचाओ के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की गई

धार। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर प्रकृति वात्सल्य गौशाला, धार में गौ पूजन का कार्यक्रम एवं गौसेवक और पशु चिकित्सकों का सम्मान किया गया । गोचर भूमि बचाओं, गाय बचाओं के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की गई। मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिन्दु परिषद के क्षेत्रीय गोरक्षा प्रमुख सोहन विश्वकर्मा उपस्थित थे। अध्यक्षता जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, समाजसेवी समंदर सिंह पटेल ने की। विशेष अतिथि के रूप में संत हरिहरानंद जी, डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा विभाग एस के मोदी , सुरेश गुर्जर विश्व हिन्दू परिषद (

बजरंग दल) विभाग संगठन महामंत्री सुरेश गुर्जर मंचासीन थे। प्रकृति वात्सल्य गौशाला अध्यक्ष धर्मेंद जोशी, संस्थापक प्रमिला शर्मा भी मंच पर उपस्थित थे। उपस्थित अतिथियों एवं धार शहर के गणमान्य नागरिकों ने गौ आरती कर संकल्प लिया कि प्रतिदिन प्रकृति वात्सल्य गौशाला, धार में गौ आरती आयोजित की जाएगी। प्रकृति वात्सल्य गौशाला के अध्यक्ष धर्मेंद जोशी ने कहा गोपाष्टमी के दिन से भगवान श्री कृष्ण पहली बार गौ विचरण कराने के लिए वन में गए थे उसी तरह आज से हम समाज की सहभागिता इस गौशाला में हो इसकी शुरुआत कर रहे है, गोचर भूमि बचाओ गाय बचाओ के हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत भी आज ही के दिन से कर रहे है। मुख्य अतिथि विहिप के क्षेत्रीय गोरक्षा प्रमुख सोहन जी विश्वकर्मा ने कहा गाय की परिक्रमा से ही सब कष्ट दूर हो जाते है। अगर हम गौवंश की रक्षा नही करेंगे तो प्रकृति के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, समाजसेवी समंदर पटेल ने कहा गोशाला और गौसेवा के लिए में तन मन धन से सदैव सहयोग दूंगा । संत श्री हरिहरानंद जी ने कहा कि पहली रोटी गाय को देने का भाव और प्रतिदिन एक रूपया गौशाला और गौमाता के लिए दान करने का भाव से ही हम गौमाता की कृपा के हकदार हो जाएंगे। प्रकृति वात्सल्य गौशाला, धार के प्रकल्पों एवं अतिथि परिचय देते हुए मोटिवेशनल स्पीकर- वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा ने बताया कि जल्द ही प्रकृति वात्सल्य गौशाला, धार अपने सेवा- संवेदना और वात्सल्य के प्रकल्पों से पुरे प्रदेश में सेवा का उदाहरण पेश कर रही है , आने वाले दिनों में यह गौशाला अपने सेवा भाव के लिए प्रदेश भर में जानी जाएगी।

पशु चिकित्सकों, समाजसेवियों, गौसेवक हुए सम्मानित...

प्रकृति वात्सल्य गौशाला, धार में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में डॉ सुधीर मोदी, डॉ रविन्द्र राठी, डॉ सुरेंद्र मौर्य, डॉ सुरेश मकवाना, डॉ राजेश डामोर, प्रसूल लिंबोदिया, डॉ अरुण धाकड आदि पशु चिकित्सकों का सम्मान किया गया। समाजसेवी सौरभ गुप्ता, घनश्याम शर्मा, राहुल शिवले ,माधव विहिप , संदीप पाटीदार गौ सेवकों (ग्वाला) किशन लश्करी, ओंकार लश्करी, गिरधारी मालवीय , मूलचंद लश्करी एवं उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वास पांडे, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र त्रिपाठी , राजेश शर्मा , जिला भाजपा मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, पर्यावरणविद सचिन दवे ,घनश्याम शर्मा, डॉ. तरूण जोशी, लालू यादव, अवध द्विवेदी ,पवन अग्रावत , रीमा राठौर , ,प्रवीण शर्मा ,मोतीलाल जोशी ,नारायण जोशी, राजीव जोशी , सतीश सोनी ,सूर्या दुबे, विजय दवे, निशा शर्मा , रामप्रसाद रघुवंशी, कमल बोरीवाल ,नीलेश जोशी, भगवती जोशी, जगदीश जोशी ,नवीन चौहान ,अजय गोयल, विजय अग्रवाल, अजय जोशी, श्रीकान्त द्विवेदी अशोक व्यास ,प्रेम रावल, जितेंद पंड्या ,पुनीत तिवारी, राजेश जोशी, राजेश धोका, विजय गवली, सतिश पाल, विजेंद्र बना गेंदालाल बमनका आदि उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रवीण शर्मा ने किया। आभार रीमा राठौर ने व्यक्त किया। जानकारी प्रकृति वात्सल्य गौशाला,सचिव धार विजया शर्मा ने दी।

21 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहीं नर्सिंग ऑफिसर

ड्रग्स की सप्लाई में संलिप्त बताया, सहेली से 50 हजार ठगे, ओडिशा, पंजाब के नंबर से आए थे कॉल

खंडवा (नप्र)। खंडवा के जिला अस्पताल में पदस्थ एक नर्सिंग ऑफिसर कंचन इनवाती 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहीं हैं। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच से फर्जी फोन और वीडियो कॉल के जरिए आरोपियों ने नर्स को ड्रग्स सप्लाई में इन्वॉल्व बताया। मोबाइल हैक कर किसी से संपर्क ना करने की धमकी दी। पानी पीने के लिए भी उठकर जाने नहीं दिया। वह अपने घर में शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शनिवार सुबह 11 बजे तक मोबाइल के सामने बैठी रहीं।

मामले का खुलासा नर्स की सहेली रेणुका कोड़ापे के साथ उसी समय हुई 50 हजार की ठगी से हुआ। डिजिटल अरेस्टिंग के दौरान ही नर्स की सहेली रेणुका कोड़ापे उससे मिलने आई थी। वह कैमरे में आ गई। बदमाशों ने उसे भी धमकाया और मोबाइल नंबर मांगा। कहा कि तुम भी तुम्हारी सहेली के साथ ड्रग्स की तस्करी करती हो। अलग कमरे में जाओ और हमसे बात करो। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

सहेली से 50 हजार ले लिए- रेणुका कोड़ापे कमरे में पहुंची और घबराकर 50 हजार रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया। पैसा देने के बाद रेणुका बाथरूम के लिए गई और खिड़की से चिट्ठी लिखकर पड़ोस की आंटी को दी।

इधर, नर्स के बाहर न आने से मकान मालिक और परिचित परेशान होकर जब दरवाजा पीटने लगे तो वह हिम्मत कर मोबाइल के सामने से उठी। नर्स ने अपने परिचित और मकान मालिक को पूरा घटनाक्रम बताकर रोने लगी। इसके बाद परिजन मामले की शिकायत करने एसपी कार्यालय पहुंचे। जहां सायबर क्राइम ब्रांच में लिखित में शिकायत की।

पीड़िता नर्स कंचन बोली- वर्दी में थे बदमाश, डिजिटल अरेस्ट वारंट डाला तो मैं डर गई

शुक्रवार दोपहर 1 बजे मैं अपने कमरे में थी। तब मेरे मोबाइल पर + 991545658570 से कॉल आया। इसके बाद 9348389952 से वीडियो कॉल कर सामने वाले ने कहा कि आपके नाम से एक पार्सल राजेश गोयल जो कि ड्रग माफिया के नाम से जा रहा था। पार्सल में लैपटाप, 6 मोबाइल, 5 पासपोर्ट, 4 आधार कार्ड और 150 ग्राम ड्रग्स मिला है। पार्सल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको डिजिटल अरेस्ट किया है। आपके ऑनलाइन बयान दर्ज किए जाएंगे। इतना सुनकर मैं डर गई। तब सामने से वीडियो कॉल कर रहे शख्स ने कहा कि हमारे डीएसपी राजेंद्र पाल राजपूत आपसे बात करेंगे। जिसके बाद 6026394817 से काल करके उक्त युवक ने कहा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।

शिव और कृष्ण भक्ति रसपान से भक्त हो रहे सराबोर...

नर्मदापुरम। भक्ति और आध्यात्म शक्ति का केंद्र नर्मदापुरम में इन दिनों आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुख्य सूत्रधार केंद्र साबित हो रहा है। एक तरफ धर्माचार्य सोमेश परसाई श्रीसवा करोड़ शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक कार्यक्रम के जरिए हजारों लोगों को शिव आराधना से जोड़कर शिव भक्त के जरिए आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग आसान कर रहे तो दूसरी ओर स्थानीय इस्कॉन मंदिर परिवार प्रमुख प्रणव दास प्रभु नगर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में श्री हरिनाम संकीर्तन और दीप-दान के जरिए कृष्ण भक्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार से लोगों को जोड़कर उनमें आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत का बीजारोपण करने में जुटे हुए हैं। सप्त दिवसीय श्री सवा करोड़ शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक आयोजन के जरिए बड़ी संख्या में शिवभक्त पूरे विधि-विधान से रुद्री निर्माण कर धर्माचार्य के निर्देश पर निर्मित रुद्रियों की पूजा अर्चना करते हुए आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रहे तो उधर कार्तिक मास में भगवान दामोदर लीला का आंनद लेते हुए कृष्ण भक्त तन्मयता से दीप-दान कर आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर रहे। रुद्री निर्माण के चौथे दिन जहां हजारों शिव भक्तों ने रुद्री निर्माण और रुद्राभिषेक कर आज आध्यात्मिक सुख प्राप्त किया वहीं नगर के समीपस्थ ग्राम पथौड़ी में श्री हरिनाम संकीर्तन और दीप-दान में सैकड़ों लोगों ने भागीदारी कर कृष्ण भक्ति का अलौकिक आनंद लिया सुबह नो साढ़े नौ बजे नगर से तीन किलोमीटर दूर कुलामढ़ी पंचायत के अन्तर्गत आने वाले पथौड़ी ग्राम के निवासी ग्राम में हरिनाम संकीर्तन सुनकर चौंक पड़े मृदंग, करताल, घंटों की ध्वनि के साथ सुनाई देने वाले हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे की नांद ने उन्हें घरों से झांकने को मजबूर कर दिया, ग्राम की गली से निकलने वाली हरिनाम संकीर्तन की टोली द्वारा गाए जा रहे हरिनाम संकीर्तन को सुनकर वे प्रफुल्लित हुए और कृष्ण भक्तों का हरिनाम संकीर्तन

में साथ देने लगे। ग्राम के शुरू हुए मंदिर से इस दौरान ग्राम के अंतिम छोर पर बने मंदिर तक संकीर्तन करती इस्कॉन मंदिर परिवार की टोली ने पूरे ग्राम को कृष्ण मय वातावरण से गुंजा दिया, ग्रामीणों के साथ इस दौरान दामोदर अष्टक पाठ के साथ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दीप-दान किया साथ ही कृष्ण भक्ति को लेकर प्रवचन हुए। प्रणव दास प्रभु ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान का नाम हमें भगवान से जोड़ता है, भगवान से जुड़कर ही हम धर्म से जुड़ते हैं और भगवान से जुड़ने का एक मात्र उपाय- हरिनाम संकीर्तन के जरिए भगवान का नाम लेकर जुड़ सकते हैं। प्रभु जी ने बताया कि हरिनाम संकीर्तन से आत्मा प्रसन्न होती हैं, आत्मा जब परमात्मा का नाम लेती है तो प्रसन्नता होती है। प्रभु जी ने कहा कि जैसे हम अपने माता-पिता की छत्रछाया में प्रसन्न रहते हैं और उनसे से अलग होकर दुखी हो जाते वैसे ही हम भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो प्रसन्न होते हैं और उनसे अलग होते ही दुखी महसूस करते हैं।

आराध्य सरोज का राज्य स्तरीय हांकी में चयन

सुबह सवेरे सोहागपुर

सेंट पैट्रिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के कक्षा 7 वीं के छात्र आराध्य सरोज का राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। उल्लेखनीय है कि आराध्य सरोज हांकी के होनहार खिलाड़ी हैं।आराध्य सरोज 11 से 14 नवंबर तक भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता में नर्मदापुरम संभाग का प्रतिनिधित्व करेगा। शाला प्राचार्य फादर दिलीप मिंज ,ब्लॉक क्रीड़ा अधिकारी हेमराजसिंह नागा ,खेल प्रशिक्षक अश्वनी सरोज ,आशु राय ,इमरान हुसैन ,जयंत रघुवंशी सहित स्टाफ ने आराध्य सरोज को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई , शुभकामनाएं देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है।

प्रदेशवासियों को आंवला नवमी की बधाई : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आंवला नवमी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान श्रीहरि विष्णु जी से प्रार्थना है कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता की वृद्धि हो, और सब पर कृपा बनाए रखें।

विश्व पटल पर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भविष्य को आकार देने में विज्ञान की अहम भूमिका है। भारत को विश्व पटल और अंतरिक्ष तक गौरवान्वित कर रहे, देश के वैज्ञानिक और विज्ञान प्रतिभाओं पर हम सभी को गर्व है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व विज्ञान दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विश्व विज्ञान दिवस की जनसामान्य को शांति, मानव-कल्याण और अत्याधुनिक तकनीक से प्रगति के लिए विज्ञान की अनिवार्यता और स्वीकार्यता के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रवादी श्री ठेंगड़ी के श्रमिक-कृषक वर्ग के उत्थान के प्रयास अनुकरणीय : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच एवं भारतीय किसान संघ के संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की जयंती पर नमन किया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि राष्ट्र पुनर्निर्माण में श्री ठेंगड़ी का क्रांतिकारी योगदान अविस्मरणीय हैं। देश के वंचित, श्रमिक-कृषक वर्ग के उत्थान और कल्याण के उनके प्रयास अनुकरणीय हैं।

विश्व टीकाकरण दिवस

सर्वाइकल कैंसर, मलेरिया को टीकाकरण में जोड़ने की तैयारी

भोपाल (नप्र)। अब एक हेक्सावैलेंट टीका उपलब्ध है, जो एक ही डोज में 6 बीमारियों - डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी), टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो से बचाव करता है। इस टीके के साथ नई तकनीकों का भी उपयोग किया गया है, जैसे नैजल और ओरल वैक्सीन्स, जो बच्चों को दर्द से बचाते हैं और उनका टीकाकरण आसान बनाते हैं।

इससे बच्चों को न तो दर्द का सामना करना पड़ता है और न ही डर का। समय पर टीकाकरण बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में कई अहम टीके

नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं।

मप्र के इम्यूनाइजेशन अधिकारी संतोष शुक्ला बतते हैं कि 1978-80 में पोलियो उन्मूलन के लिए ओरल पोलियो वैक्सीनेशन शुरू किया गया। 2023 में जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) का टीका जोड़ा गया, जिससे दिमागी बुखार से सुरक्षा मिली। 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान ने महामारी से बचाव में अहम भूमिका निभाई। भविष्य में मलेरिया और सर्वाइकल कैंसर के टीके भी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है, जल्द ही सरकारी टीकाकरण का हिस्सा बनेगा, ताकि यह सभी के लिए उपलब्ध हो सके। शुक्ला बताते हैं कि भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1802 में चेचक के टीके से हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संगठित टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ।

उपचुनाव के बाद होगी कलेक्टर गाइडलाइन की बैठक

भोपाल में होल्ड पर है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव; सांसद-विधायक कर चुके विरोध

भोपाल (नप्र)। भोपाल की कुल 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट 5 से 200 प्रतिशत तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर है। सांसद आलोक शर्मा समेत विधायकों और क्रेडाई के विरोध के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे होल्ड पर रख दिया। अब प्रशासन सुझाव के लिए जनप्रतिनिधियों की बैठक कर रहा है, जो बुधनी-विजयपुर उप चुनाव के बाद होगी।

मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सांसद शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी अभी बुधनी-विजयपुर के साथ महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव में व्यक्त है। यहां 12 नवंबर को वोटिंग होगी। इसलिए 15 नवंबर के बाद भोपाल की कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर बैठक हो सकती है। सूत्रों की माने तो बढ़े गाइडलाइन के प्रस्ताव से जनप्रतिनिधि नाराज हैं। इसलिए वे इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं।सांसद आलोक शर्मा और क्रेडाई प्रस्तावित गाइडलाइन का

विरोध जमा चुके हैं।

सांसद-विधायक नहीं चाहते, गाइडलाइन बढ़े- बता दें कि सांसद शर्मा प्रस्तावित गाइडलाइन को लेकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। वहीं, विधायकों की नाराजगी भी देखने को मिल चुकी है। वे नहीं चाहते कि गाइडलाइन बढ़े, क्योंकि इसी साल एक बार गाइडलाइन बढ़ चुकी है। सांसद शर्मा ने बताया, गाइडलाइन नहीं बढ़ना चाहिए। मीटिंग में यह सुझाव रखेंगे।

राजस्व में भी वृद्धि नहीं- मीक ने बताया, इस प्रकार की नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव राज्य के राजस्व पर भी पड़ सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के अनुभव से यह साबित हुआ है कि अत्यधिक सर्किल रेट से संपत्ति लेन-देन में कमी आती है, जिससे राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती।

100 इलाकों में 20 प्रतिशत तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव- बता दें कि, भोपाल में कुल 3883 लोकेशन है। इनमें शहर में 3091 और ग्रामीण में 792 लोकेशन शामिल हैं। 3641 लोकेशन में रेट नहीं बढ़ाए और बाकी लोकेशन पर वृद्धि का प्रस्ताव है। इस बार 9 नई लोकेशन भी जोड़ी गई है।

5 से 200 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव

बता दें कि भोपाल में रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर में एवरेज 8.55 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधायक भगवानदास सबनानी की आपत्ति के बाद 13 लोकेशन हटा दी गई है। यानी, 240 लोकेशन पर रेट बढ़ेंगे।

क्रेडाई भी जता चुका है विरोध

क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के अध्यक्ष मनोज मीक समेत क्रेडाई सदस्यों ने भी वित्त मंत्री देवड़ा से मुलाकात की थी। अध्यक्ष मीक ने बताया, भोपाल में सर्किल रेट में प्रस्तावित अत्यधिक वृद्धि का रियल एस्टेट उद्योग, आम जनता और प्रधानमंत्री के 'हाउसिंग फॉर ऑल' मिशन के लक्ष्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। पिछले दशक में इंदौर के मुकाबले भोपाल में सर्किल रेट में कई गुना वृद्धि पहले ही हो चुकी है। जिससे संपत्ति बाजार अस्थिर हो गया है।

इसका परिणाम यह हुआ कि भोपाल में निवेश में कमी आई है और संपत्तियों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया है। लगभग सर्किल रेट बढ़ाने से प्रॉपर्टी टैक्स में सीधी वृद्धि होती है। जिससे आमजन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए गाइडलाइन को खारिज किया जाना चाहिए।

कक्षा-6 से 8 तक के

स्कूलों में माह में कम से कम एक शनिवार को होगा बैगलेस-डे

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में कक्षा-6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों का समग्र विकास हो, इसके लिये बैगलेस-डे के दिन बच्चों को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने का निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। इस दिन बच्चों के बीच पढ़ाई के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं व्यावहारिक गतिविधियाँ की जायेंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला शिक्षाधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी किये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में यह प्रावधान रखा गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 21वीं सदी के कौशल से परिचित हो सकें, इसके लिये कक्षा-6 से 8 तक के स्कूल के बच्चों के लिये प्रत्येक माह में न्यूनतम एक शनिवार को बस्ते-विहीन दिवस का आयोजन हो। इन दिवसों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल की जानकारी दी जाये। बैगलेस-डे के लिये शाला के प्राचार्य एवं शिक्षकों को चर्चा कर गतिविधियों का कैलेण्डर तैयार करने के लिये भी कहा गया है।

बढ़ते बाल विवाह रोकने के लिए म.प्र.सरकार का लाडो अभियान

शादी के कार्ड पर दुल्हा-दुल्हन की उम्र जरूरी

कैटरर्स, पंडित, बैंड-टेंट और होटल वाले... सब हो जाएं सावधान

सागर(नप्र)। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है 'लाडो अभियान'। इस अभियान के तहत शादी के कार्ड पर वर-वधू की कानूनी उम्र का जिक्र करना अनिवार्य होगा।इतना ही नहीं, कैटरर्स, पंडित, बैंड वाले, टेंट वाले और होटल वालों को भी वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

बाल विवाह के बढ़ते मामलों पर लगेगी लगाम- एमपी में बढ़ते बाल विवाह के मामलों को देखते हुए मोहन यादव सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब शादी के कार्ड पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि वर और वधू दोनों ही शादी की कानूनी उम्र के हैं। इसके अलावा, शादी से जुड़ी सभी सेवाएं देने वालों, जैसे कि कैटरर्स, पंडित, बैंड वाले, टेंट वाले और होटल वालों को भी वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र देखना होगा। तभी वह अपनी सेवाएं दे पाएंगे।

हर जिले में बनेगी टास्क फोर्स-इस अभियान को सफल बनाने के लिए एमपी के हर जिले में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। इस टास्क फोर्स में अलग-अलग विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की पहचान करें और उनकी निगरानी करें ताकि उनका बाल विवाह न हो सके।

सागर में हुई शुरूआत-सागर जिले में जिला प्रशासन ने इस अभियान की शुरुआत कर दी है। यहां अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को शामिल करके एक टास्क फोर्स बनाई गई है। यह टास्क फ़ोर्स अपने-अपने इलाकों में जाकर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके बाद इन बच्चों पर नजर रखी जाएगी ताकि इनकी शादी ना हो सके।

ग्रामीण इलाकों पर फोकस-इसके अलावा, अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में टीमें बनाई जाएंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि जिन बच्चों की पहचान की गई है उनका बाल विवाह तो नहीं हो रहा है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा।

क्या है लाड़ो अभियान

'लाडो अभियान' के तहत, अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में ब्लॉक और तहसील स्तर पर उड़नदस्ते बनाए जाएंगे। इन उड़नदस्तों का काम होगा शादियों में सेवाएं देने वालों, जैसे कि कैटरर्स, बैंड वालों, टेंट वालों को जागरूक करना। इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा और उन्हें बाल विवाह में अपनी सेवाएं न देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने दी जानकारी-जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सामूहिक विवाह के समय अधिकारी वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी केंद्र के रिकॉर्ड की जांच करेंगे। अगर ये दस्तावेज़ नहीं मिलते हैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा।

सामूहिक विवाह पर भी लागू है नियम-इसके अलावा, सामूहिक विवाह करवाने वालों से यह शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि वह अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं होने देंगे। प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर, पंडित, बैंड वाले, और समाज के मुखिया से भी अनुरोध किया जाएगा कि वह वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र देखने के बाद ही अपनी सेवाएं दें।

शादी के कार्ड पर साफ-साफ लिखी जाए उम्र-साथ ही, यह भी निर्देश दिया जाएगा कि शादी के कार्ड पर यह बात साफ-साफ लिखी हो कि वर और वधू कानूनी तौर पर शादी करने की उम्र के हैं। इसके लिए जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस को निर्देशित किया जाएगा।

सरकार ने एक्टिव किए सभी विभाग-बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने सभी विभागों को 'लाडो अभियान' के तहत एक्टिव कर दिया है। इस मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा जहां लोग बाल विवाह की सूचना दे सकेंगे। यह कंट्रोल रूम जिला मुख्यालय पर होगा। इसके अलावा, हर प्रखंड में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

हेल्पलाइन नंबर भी होंगे जारी-इसके साथ ही, पुलिस थाना, चाइल्डलाइन, कलेक्टर, अनुविभागीय कार्यालय, जिला/परियोजना कार्यालय (आईसीडीएस) और अन्य विभागों के अधिकारियों के फ़ोन नंबर भी जारी किए जाएंगे ताकि लोग आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें।

शहडोल में 40 लाख की ठगी का अनोखा मामला आया सामने

गुरुजी की एक गलती के कारण 40 लाख की पड़ी चाय!

अब शहडोल में बैंक से लेकर पुलिस परेशान, यह है मामला

शहडोल (नप्र)। जिले के एक हेड मास्टर को बैंक के कर्मचारियों ने ही चूना लगा दिया। मामला एक-दो लाख का नहीं, पूरे 40 लाख रुपए की ठगी का है। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के हेडमास्टर गुलाब हलवाई ने मामले की शिकायत की। इसके बाद सोहागपुर थाना में निजी बैंक के वरुण मिश्रा नामक कर्मचारी निवासी शहडोल तथा अमित कुमार गौतम निवासी रीवा के विरुद्ध धारा 420, 120 बी का अपराध दर्ज कर लिया गया है।

एसे की ठगी-पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार निजी बैंक का कर्मचारी बताने वाले वरुण मिश्रा से शिक्षक गुलाब सिंह हलवाई की जान पहचान थी। इस नाते वह उनके घर आता जाता था। उसने निजी बैंक में उनका अकाउंट खुलवा दिया। बीते वर्ष वह घर आया और बैंक की फायदेमंद स्कीम बताते हुए कुछ राशि एफडी कराने को कहा। झांसे में आकर उन्होंने 20 हजार, 50 हजार व कुछ और रकम किश्तों में कई बार दे दी। वरुण ने राशि के साथ आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों की जानकारी ले ली। कुछ दिनों बाद वह अपने साथी अमित कुमार गौतम के साथ फिर घर आया और फिर से बैंक की स्कीम बताई। चूंकि वह दोनों परिवार के साथ घुलमिल चुके थे, इसलिए उन्होंने जो दस्तावेज मांगे गुलाब हवाई वह देते चले गए। दोनों ने उनका फोन पे चालू कराया। बैंक का एटीएम सहित नेटबैंकिंग भी बनवा लिया।

जमा रसीद के नाम पर की टालमटोल-शिक्षक जब जमा आदि की रसीद मांगते तो बाद में दे देंगे का बहाना बनाते रहे। कुछ समय बाद शिक्षक जब बैंक गए तो पता चला कि उनके खाते से लगभग 40 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। तब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। बैंक गए तो पता चला कि दोनों कर्मचारी बैंक नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद शिक्षक ने शिकायत दर्ज कराई।

शातिर दिमाग थे दोनों-इस संबंध में शिक्षक गुलाब हलवाई ने बताया कि वरुण मिश्रा उनके घर आया था और उनसे खाता खुलवाने के नाम पर राशि ली थी। इस बीच दोनों के संबंध जब घनिष्ठ हो गए। कई बार गुलाब हलवाई जब चाय बनाने के लिए जाते तो अपना मोबाइल वहीं छोड़ जाते थे। तभी वरुण ने उनके मोबाइल से नेट बैंकिंग चालू करके उसका पासवर्ड और यूजर नेम अपने पास रख लिया और मेरे खाते से पैसा निकाल कर अपने दोस्त अमित कुमार गौतम के खाते में ट्रांसफर कर दिए।

पुलिस कर रही मामले की जांच-इस संबंध में सोहागपुर थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र मणि पांडेय का कहना है कि शिक्षक गुलाब हलवाई की शिकायत पर वरुण मिश्रा और अमित गौतम के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। रकम दोनों लोगों के खातों में ट्रांसफर हुई हैं।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

छत्तीसगढ़ का राजनीतिक भविष्य तय करेगा रायपुर दक्षिण

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस में लड़ाई चरम पर नजर आ रही है। भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है तो कांग्रेस के नेता भी मैदान में उतर गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में लग गए हैं, पर कांग्रेस के साथ समस्या यहां उसका जमीनी आधार न होना है। बृजमोहन अग्रवाल यहां से आठ बार लगातार विधायक रहे। बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वे जनसंपर्क से लेकर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क में जुटे हैं। सुनील सोनी जाने-पहचाने चेहरे हैं। एक बार सांसद और महापौर रह चुके हैं, वहीं उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने से भाजपा में बगावत जैसे स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। दावेदार भी सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार करते दिख रहे हैं। कांग्रेस जरूर सुनील सोनी पर सक्रिय न रहने का आरोप लगा रही है, पर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को लेकर कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है। दावेदार अब भी आकाश शर्मा को स्वीकारने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। फिर आकाश शर्मा रायपुर दक्षिण के लिए नए भी हैं। कांग्रेस को यहां मुस्लिम और ब्राम्हण वोटों पर भरोसा है, लेकिन निर्दलीय मुस्लिम प्रत्याशी कितना वोट काटते हैं, इस पर भी गणित निर्भर करेगा। रायपुर दक्षिण का चुनाव विष्णुदेव साय सरकार के लिए अग्नि परीक्षा जैसी है। यहां जीतकर सरकार अपनी ताकत दिखाना चाहती है। रायपुर दक्षिण का चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ के लिए आगे का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा,क्योंकि अगले कुछ महीनों बाद नगरीय निकायों और पंचायतों के भी चुनाव होने हैं। रायपुर दक्षिण में जीत-हार के साथ लीड भी महत्वपूर्ण होगी।

नए डीजीपी के लिए कब शुरू होगी कवायद

माना जा रहा है कि डीजीपी अशोक जुनेजा को अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा,ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से नए डीजीपी के लिए भारत सरकार को जल्द पैनल भेजा जाएगा या केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार किया जाएगा। इस मुद्दे पर प्रशासनिक गलियारे पर चर्चा शुरू हो गई है। डीजीपी अशोक जुनेजा को भारत सरकार ने अगस्त महीने में छह माह की सेवावृद्धि दी थी। वे फ़रवरी 25 तक रहेंगे। कहा जा रहा है कि डीजीपी के रिटायरमेंट के करीब तीन महीने पहले नए डीजीपी के लिए भारत सरकार को अफसरों के नामों का पैनल भेजने की परंपरा रही है, परंतु इसका पालन नहीं होता। कभी-कभी तो ऐन वक्त पर पैनल भेजा जाता है या फिर एक्टिंग डीजीपी नियुक्त कर बाद में प्रक्रिया पूरी की जाती है। छत्तीसगढ़ में दो बार एक्टिंग डीजीपी नियुक्त कर बाद में प्रक्रिया पूरी की गई। अभी डीजीपी की दौड़ में अरुण देव गौतम, पवनदेव और हिमांशु गुप्ता है। जनवरी 2025 में प्रदीप गुप्ता भी 30 साल की सेवा पूरी कर लेंगे और डीजी के लिए पात्र हो जाएंगे।

वित्त और लोक निर्माण विभाग में तालमेल की कमी

चर्चा है कि राज्य के लोक निर्माण विभाग और वित्त विभाग में तालमेल की कमी के चलते सड़कें संवर नहीं पा रही हैं। कहते हैं साय सरकार के साथ पिछली सरकार में स्वीकृत सड़कों के लिए टेंडर अटका पड़ा है। कहा जा रहा है कि नए सड़कों के लिए वित्त से मंजूरी लेने का काम लोक निर्माण विभाग का है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। विष्णुदेव साय सरकार में लोकनिर्माण विभाग उपमुख्यमंत्री अरुण साव के पास है,जबकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं। जब अरुण साव प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, तब ओपी चौधरी उनके महामंत्री थे। ओपी चौधरी 2005 बैच के आईएएस रहे हैं। अभी 2005 बैच के आईएएस मुकेश बंसल वित्त सचिव हैं, जबकि 2002 बैच के आईएएस कमलप्रीत सिंह लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं।

मंत्री जी के अरमानों पर फिरा पानी

खबर है कि एक उद्योगपति छत्तीसगढ़ के एक सामान्य जिले में बड़ा उद्योग लगा रहे हैं, इसके लिए उन्हें सैकड़ों एकड़ जमीन की दरकार पड़ी। उद्योगपति ने एक व्यक्ति की करीब 30 एकड़ जमीन बाजार भाव में सौदा कर लिया। मंत्री जी को जब इसकी भनक लगी तो वे अधिक कीमत देने की वकालत करने लगे और उस व्यक्ति को जमीन नहीं बेचने की सलाह दी। ऊँचे भाव के ख्वाब में व्यक्ति का मन भी डोलने लगा। अब उघोगपति तो उद्योगपति ठहरा, उसे तो अपना नफा-नुकसान देखना था। उद्योगपति ने उस व्यक्ति की जमीन ही खरीदना कैंसल कर दिया। मंत्री जी को इस बात की जानकारी मिलने पर जमीन खरीदने के लिए उद्योगपति पर दबाव डलवाया। दबाव काम नहीं आया। और मंत्री जी के साथ 'माया मिली न राम'वाली कहावत चरितार्थ हो गई।

बिरसा मुंडा कार्यक्रम में आनलाइन जुड़ेंगे मोदी

आदिवासियों के बड़े नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर रायपुर में 15 नवंबर को सरकारी स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिलों में भी कार्यक्रम होंगे। बताते हैं इस कार्यक्रम में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनलाइन जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्तर पर बिरसा मुंडा को लेकर पहली बार बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस के राज में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को कार्यक्रम का रिवाज था। विष्णुदेव साय की सरकार ने 9 अगस्त को कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था, उसके बदले बिरसा मुंडा की जयंती को चुना है। बिरसा मुंडा की जयंती पर रायपुर में कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था। झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है। झारखंड छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है। छत्तीसगढ़ के कई भाजपा नेता झारखंड में चुनाव प्रचार में भी लगे हैं। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम से झारखंड के जनजातीय समाज के लिए संदेश भी होगा।

अब केदार भी नए रायपुर की तरफ

कहते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बाद अब वन मंत्री केदार कश्यप भी नए रायपुर के बंगले में गृह प्रवेश करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि केदार कश्यप 13 नवंबर को नए रायपुर के बंगले में जाएंगे। रामविचार नेताम नए रायपुर के बंगले में रहने लगे हैं, उन्होंने रायपुर में कोई सरकारी बंगला नहीं लिया था। मुख्यमंत्री श्री साय नए रायपुर के बंगले में पूजा-पाठ के बाद प्रवेश कर लिया है, लेकिन रायपुर में मुख्यमंत्री निवास अभी नहीं छोड़ा है। मंत्री केदार कश्यप ने भी रायपुर में बंगला लिया है। अब देखते हैं नए रायपुर के बंगले में गृह प्रवेश के बाद पुराना आशियाना छोड़ते हैं या नहीं। केदार कश्यप अभी जिस बंगले में रहते हैं, उस बंगले में रमन मंत्रिमडल में मंत्री रहते भी रहे हैं।

सवाल पुलिस की साख का

माना जा रहा है कि शुक्रवार को भिलाई में एक अपराधी के एनकाउंटर से पुलिस की साख में कुछ सुधार होगा। प्रदेश में लगातार अपराध और चाकूबाजी की घटनाओं के साथ कवर्धा, सूरजपुर और बलरामपुर की घटना ने राज्य में पुलिस की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। कहा जा रहा है कि एनकाउंटर से अपराधियों में कुछ तो खौफ पैदा होगा। बढ़ते अपराध को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया था। कांग्रेस ने सूरजपुर और बलरामपुर की घटना को लेकर सरकार को घेरा भी। कांग्रेस के हमले के खिलाफ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव को उतरना पड़ा। अब कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपना ली है।